

अर्थव्यवस्था की स्थिति

कोविड-19 महामारी के चलते पिछले दो साल विश्व अर्थव्यवस्था के लिए कठिन रहे हैं। संक्रमण की नयी लहरों, आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान, और हाल ही में मुद्रास्फीति के कारणवश नीति-निर्माण के लिए यह समय विशेषतः चुनौतीपूर्ण रहा है। इन चुनौतियों की तत्काल प्रतिक्रिया के रूप में भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों एवं व्यापार क्षेत्र के लिए एक विस्तृत सुरक्षा-जाल का गठन किया। इसके उपरांत, बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की गयी, ताकि मध्यम-अवधि की मांग पुनः बढ़े, एवं अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विस्तार के लिए आपूर्ति-पक्ष उपायों को कृतसंकल्प लागू किया गया। यह अध्याय दर्शाता है कि कैसे यह लचीला और बहुस्तरीय दृष्टिकोण आंशिक रूप से “एजाइल” (चुस्तदुरुस्त) कार्यप्रणाली पर आधारित है जो “फीडबैक-लूप” (प्रतिक्रिया-पाश) और “रीयल-टाइम डेटा” (वास्तविक-काल आंकड़ों) का उपयोग करती है।

वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2020-21 में 7.3 प्रतिशत संकुचन के बाद, अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2021-22 में 9.2 प्रतिशत के विस्तार की उम्मीद है। कुल मिलाकर, आर्थिक गतिविधि पूर्व-महामारी/2019-20 के स्तर से उभर चुकी है। लगभग सभी संकेतकों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में कोविड-19 की “दूसरी लहर” का आर्थिक प्रभाव पहली लहर के दौरान पूर्ण-लॉकडाउन चरण की तुलना में बहुत कम था, यद्यपि स्वास्थ्य प्रभाव अधिक गंभीर था।

महामारी से कृषि और संबद्ध क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुए हैं और पिछले वर्ष में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि के बाद इस क्षेत्र के 2021-22 में 3.9 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। 2020-21 में 7 प्रतिशत संकुचन के पश्चात्, उद्योग के सकल मूल्य वर्धन (खनन और निर्माण सहित) में 2021-22 में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि अग्रिम तौर पर अनुमानित है। सेवा क्षेत्र महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, विशेष रूप से ऐसे खंड जिनमें मानव संपर्क शामिल हैं। पिछले साल के 8.4 फीसदी के संकुचन के बाद इस वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र के 8.2 प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान है।

2021-22 में कुल खपत में 7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जिसमें सरकारी खर्च का महत्वपूर्ण योगदान है। सकल अचल पूंजी निर्माण के महामारी पूर्व के स्तर से अधिक होने में भी बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का योगदान है। वस्तुओं और सेवाओं दोनों का निर्यात 2021-22 में असाधारण रूप से मजबूत रहा है, वहीं घरेलू मांग और अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते आयात में भी मजबूती आई है।

टीकाकरण कार्यक्रम में अधिकांश आबादी के शामिल होने, आर्थिक गति तीव्र होने, और आपूर्ति-पक्ष

सुधारों के संभावित दीर्घकालिक लाभों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद में 8.0-8.5 प्रतिशत की वृद्धि देखने की अच्छी स्थिति में है।

बहरहाल, वैश्विक वातावरण अभी भी अनिश्चित बना हुआ है। लेखन के समय ओमिक्रोन संक्रमण के रूप में एक नई लहर दुनिया भर में फैल रही थी, अधिकांश देशों में मुद्रास्फीति बढ़ गई थी, और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक तरलता निकासी का दौर शुरू किया जा रहा था। इसलिए, भारत के वृहद-आर्थिक स्थिरता संकेतकों और उनकी उपरोक्त दबावों के विरुद्ध समर्थन प्रदान करने की क्षमता को जांचना विशेषतः महत्वपूर्ण है।

वैश्विक महामारी के कारण हुए सभी व्यवधानों के बावजूद, पिछले दो वर्षों में भारत का भुगतान संतुलन अधिशेष में रहा। इससे भारतीय रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार जमा होता रहा, और 31 दिसंबर 2021 को यह 634 बिलियन डॉलर था। यह 13.2 महीने के आयात के बराबर है और देश के विदेशी ऋण से अधिक है। पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, निरंतर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बढ़ती निर्यात आय का संयोजन 2022-23 में संभावित वैश्विक मौद्रिक तरलता के प्रतिगमन के विरुद्ध उपयुक्त प्रतिरोधक प्रदान करेगा।

अर्थव्यवस्था को दिए गए वित्तीय समर्थन के साथ-साथ स्वास्थ्य प्रतिक्रिया में हुए व्यय के कारण 2020-21 में राजकोषीय घाटे और सरकारी ऋण में वृद्धि हुई। हालांकि, 2021-22 में सरकारी राजस्व में एक मजबूत पलटाव हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार वित्तीय समर्थन और पूंजीगत व्यय में वृद्धि को कायम रखते हुए इस वर्ष के अपने वित्तीय लक्ष्यों को सहजता से पूरा करने में सक्षम है। राजस्व में प्रबल पुनः प्रवर्तन (अप्रैल-नवंबर 2021 में राजस्व प्राप्तियों में 67 प्रतिशत की वृद्धि थी) का अभिप्राय है कि आवश्यकता की स्थिति में सरकार के पास अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय गुंजाइश है।

अनिश्चित समय के दौरान वित्तीय तंत्र दबाव का एक संभावित क्षेत्र होता है। हालांकि, भारत के पूंजी बाजारों ने कई वैश्विक बाजारों की तरह असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसकी मदद से भारतीय कंपनियों के लिए रिकॉर्ड-स्तर पर जोखिम पूंजी जुटाना संभव हुआ है। गौरतलब है कि बैंकिंग प्रणाली अच्छी तरह से पूंजीकृत है और गैर-निष्पादित आस्तियों में, महामारी के विलम्बित प्रभाव को मिलाकर भी, संरचनात्मक रूप से गिरावट आई है।

टीकाकरण केवल एक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर संपर्क-गहन सेवाओं के लिए। इसलिए, इसे अभी के लिए एक व्यापक आर्थिक संकेतक के रूप में माना जाना चाहिए। टीकाकरण अभियान के एक वर्ष में भारत ने 157 करोड़ खुराक दी हैं, जिसमें 91 करोड़ लोगों को कम-से-कम एक खुराक और 66 करोड़ लोगों को दोनों खुराक दी गयी हैं। लेखन के समय, बूस्टर और 15-18 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण प्रक्रिया भी गति पकड़ रही थी।

उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति एक वैश्विक मुद्दे के रूप में फिर से सामने आई है। भारत की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति दिसंबर 2021 में 5.6 प्रतिशत वर्ष-पर-वर्ष थी जो कि लक्षित सीमा के भीतर है। हालांकि, थोक मूल्य मुद्रास्फीति दोहरे अंकों में चल रही है। यद्यपि यह आंशिक रूप से अल्पकालिक आधार प्रभावों के कारण है, भारत को आयातित मुद्रास्फीति से सावधान रहने की आवश्यकता है, खासकर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों से।

कुल मिलाकर, वृहद-आर्थिक स्थिरता संकेतक बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 की चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अच्छी स्थिति में होने का एक कारण इसकी अनूठी प्रतिक्रिया रणनीति है। कठोर प्रतिक्रिया के लिए पूर्व-प्रतिबद्ध होने के बजाय, भारत सरकार ने एक ओर कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा-जाल का उपयोग करने का विकल्प चुना, जबकि सूचना की “बेजियन-अपडेटिंग” के आधार पर पुनरावृत्त रूप से प्रतिक्रिया दी। पिछले साल की आर्थिक समीक्षा में इस प्लारबेल रणनीति पर चर्चा की गई थी। इस लचीले, पुनरावृत्त “एजाइल” कार्यप्रणाली का एक प्रमुख प्रवर्तक 80 उच्च-आवृत्ति संकेतक (एचएफआई) का उपयोग और अत्यधिक अनिश्चितता के वातावरण में संकेतों से प्रसार को अलग करने की कला है।

भारत की प्रतिक्रिया की एक और विशिष्ट विशेषता मांग-प्रबंधन पर पूर्ण निर्भरता के बजाय आपूर्ति-पक्ष सुधारों पर जोर देना है। इन आपूर्ति-पक्ष सुधारों में कई क्षेत्रों का अविनियमन, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, 'पूर्वव्यापी कर' जैसे पुराने मुद्दों का निराकरण, निजीकरण, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन आदि शामिल हैं। इन पर संबंधित अध्यायों में विस्तार से चर्चा की गई है। यहां तक कि सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि को मांग-प्रबंधन के साथ-साथ आपूर्ति-पक्ष की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि यह भविष्य के विकास के लिए बुनियादी ढांचे की क्षमता का निर्माण करती है। इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा प्रक्रिया सुधारों के महत्व पर प्रकाश डालती है एवं अध्याय 12 आर्थिक विकास का आकलन करने के लिए उपग्रह छवियों और भू-स्थानिक डेटा - जो नूतन अविनियंत्रित क्षेत्रों में से एक हैं - के उपयोग का एक संक्षिप्त प्रदर्शन प्रदान करता है।

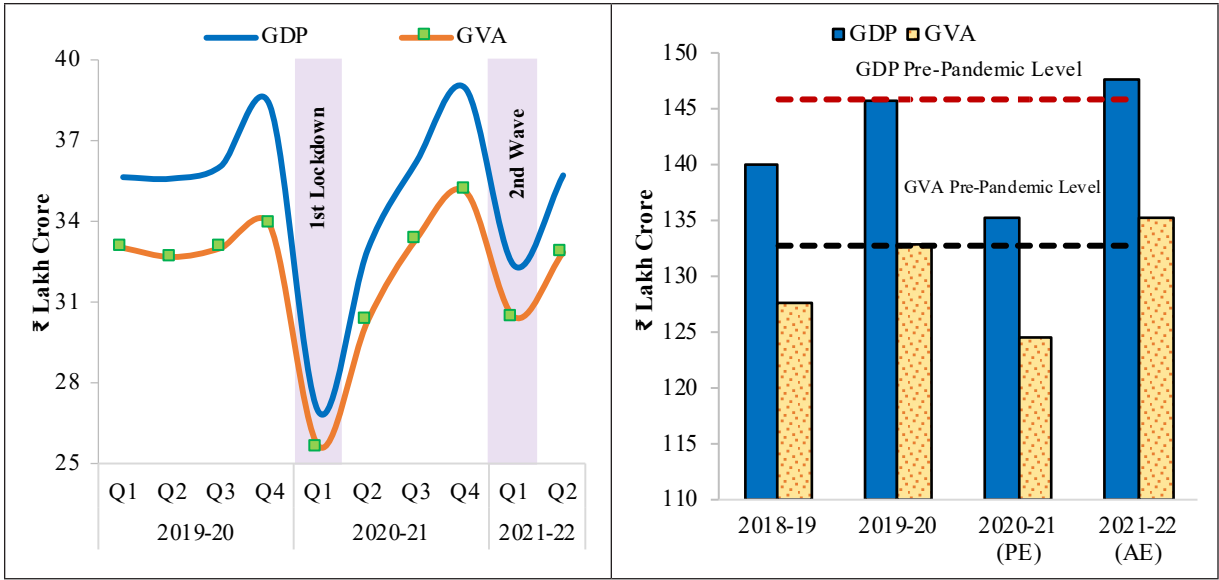
परिचय

1.1 कोविड-19 महामारी के दो साल के दौरान पुनरुत्थान लहरों, आपूर्ति-शृंखला व्यवधानों और उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति की वापसी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता से त्रस्त रही है। इसके अलावा, अगले वर्ष के दौरान प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा चलनिधि की संभावित वापसी से भी वैश्विक पूंजी प्रवाह अधिक अस्थिर हो सकता है। इस संदर्भ में, भारत में विकास पुनरुद्धार की गति के साथ-साथ व्यापक-आर्थिक स्थिरता संकेतकों की ताकत दोनों का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। टीकाकरण में प्रगति को देखना भी आवश्यक है क्योंकि यह न केवल एक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया है, बल्कि बार-बार महामारी की लहरों के कारण होने वाले आर्थिक व्यवधानों के खिलाफ एक प्रतिरोधक भी है।

अर्थव्यवस्था महामारीपूर्व स्तरों से सुधर रही है

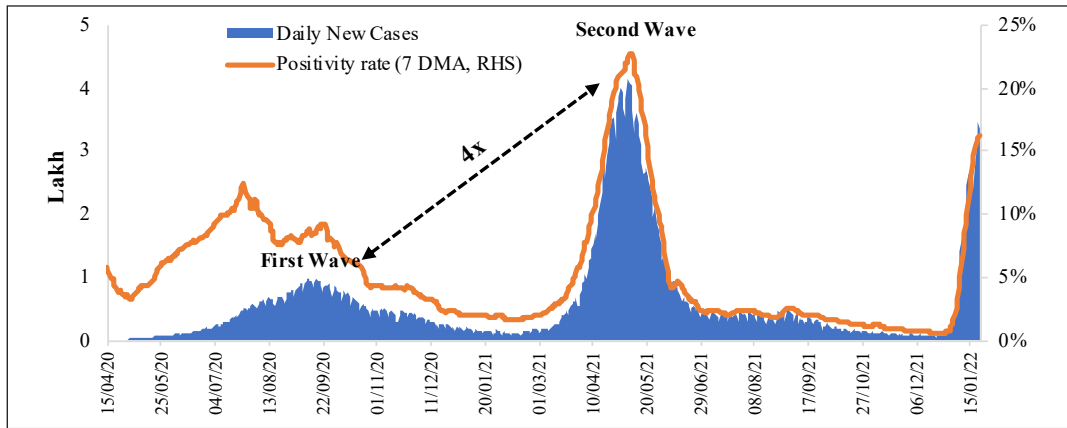
1.2 भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसा कि सकल घरेलू उत्पाद के तिमाही अनुमानों में देखा गया है, 2020-21 की दूसरी छमाही से निरंतर सुधार रही है। हालांकि, अप्रैल-जून 2021 में महामारी की दूसरी लहर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अधिक गंभीर थी, पिछले वर्ष के राष्ट्रीय लॉकडाउन की तुलना में आर्थिक प्रभाव मौन था (तालिका 1 और 2 देखें)। अग्रिम अनुमान बताते हैं कि 2021-22 में जीडीपी 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करेगी। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तविक आर्थिक उत्पादन का स्तर 2019-20 के पूर्व-कोविड स्तर को पार कर जाएगा।

चित्र 1: सकल घरेलू उत्पादन (स्थिर मूल्य, आधार वर्ष: 2011-12)



स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएसओ)

चित्र 2: कोविड-19 की लहरें



स्रोत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त डेटा
 नोट: डीएमए का मतलब डेली मूविंग एवरेज है

क्षेत्र-वार चलन

1.3 कृषि क्षेत्र महामारी से संबंधित व्यवधानों से सबसे कम प्रभावित था (चित्र 3)। इसके यह पिछले दो वर्षों में क्रमशः 3.6 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत के शीर्ष पर 2021-22 में 3.9 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है (तालिका 1)।

तालिका 1: स्थिर (2011-12) कीमतों पर जीवीए की वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)

क्षेत्र	2019-20 (पहला सं.अ.)	2020-21 (अ.अ.)	2021-22 (1 अग्रिम अ.)	2019-20 से बहाली की %
कृषि और संबद्ध क्षेत्र	4.3	3.6	3.9	107.7
उद्योग	-1.2	-7.0	11.8	104.1

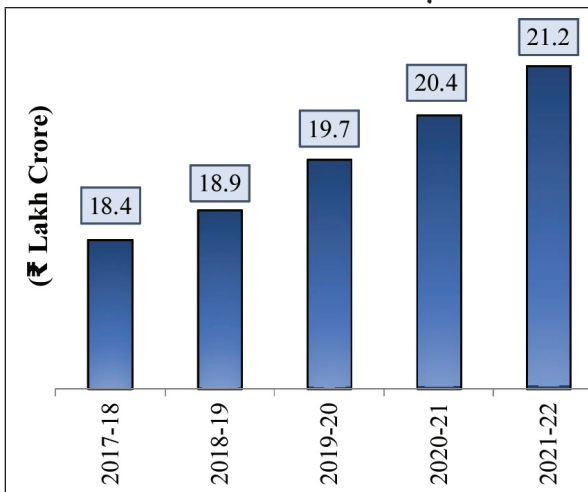
खनन और उत्खनन	-2.5	-8.5	14.3	104.6
उत्पादन	-2.4	-7.2	12.5	104.4
बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	2.1	1.9	8.5	110.5
निर्माण	1.0	-8.6	10.7	101.2
सेवाएं	7.2	-8.4	8.2	99.2
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं	6.4	-18.2	11.9	91.5
वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं	7.3	-1.5	4.0	102.5
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	8.3	-4.6	10.7	105.6
मूल कीमत पर जीवीए	4.1	-6.2	8.6	101.9

स्रोत: एनएसओ

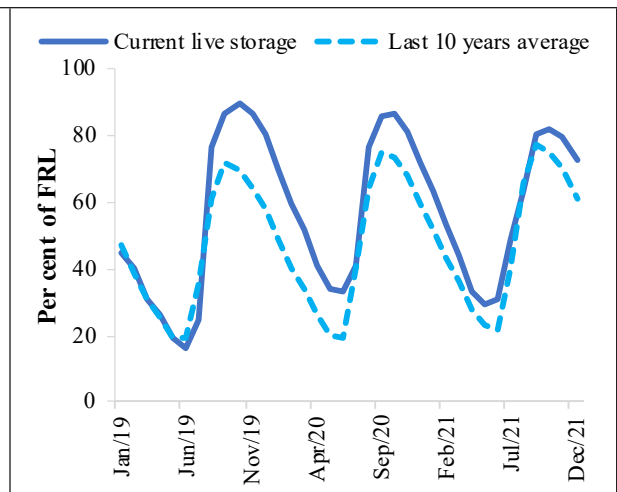
नोट: सं.अ. - संशोधित अनुमान, अ.अ. - अनंतिम अनुमान, अग्रिम अ. - अग्रिम अनुमान

1.4 जैसा कि नीचे चित्र 5 और 6 में दिखाया गया है, खरीफ और रबी फसलों के तहत बोया गया क्षेत्र और गेहूं और चावल का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रहा है। लंबी अवधि की रुझान के अनुरूप, 2021-22 के खरीफ चक्र में बोया गया क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में फिर से अधिक था (लेखन के समय रबी चक्र डेटा अधूरा था)। चालू वर्ष में, खरीफ सत्र का खाद्यान्न उत्पादन 150.5 मिलियन टन का रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज होने का अनुमान है। केंद्रीय पूल के तहत खाद्यान्न की खरीद ने 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ अपनी बढ़ती रुझान को बनाए रखा, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय के लिए अच्छा संकेत है। महत्वपूर्ण रूप से, इस क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन सरकारी नीतियां समर्थित था, जिससे महामारी संबंधी व्यवधानों के बावजूद समय पर बीज और उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित हुई। अच्छी मानसूनी बारिश से भी इसमें मदद मिली, जैसा कि जलाशय के स्तर में 10 साल के औसत से अधिक होना परिलक्षित होता है (चित्र 4)।

चित्र 3: कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का वास्तविक जीवीए



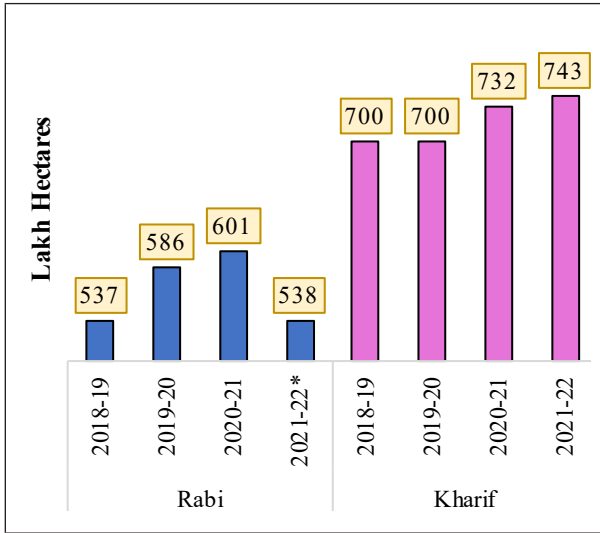
चित्र 4: जलाशय का स्तर



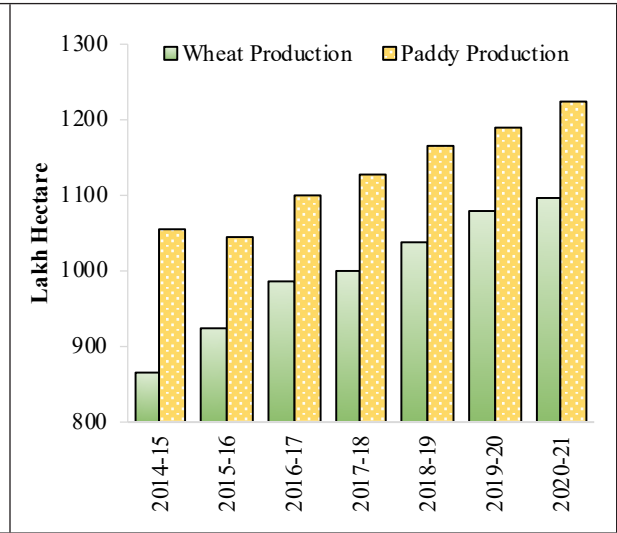
स्रोत: एनएसओ, केंद्रीय जल आयोग

नोट: एफआरएल का अर्थ पूर्ण जलाशय स्तर है

चित्र 5: खाद्यान्न के तहत बोया गया क्षेत्र



चित्र 6: गेहूँ और चावल का उत्पादन



स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय; *31 दिसंबर 2021 तक

1.5 प्राथमिक क्षेत्र के स्थिर प्रदर्शन के विपरीत, औद्योगिक क्षेत्र में 2020-21 में पहले 7 प्रतिशत का संकुचन और फिर इस वित्तीय वर्ष में 11.8 प्रतिशत का विस्तार हुआ। विनिर्माण, निर्माण और खनन उप-क्षेत्र उसी रफ्तार से वृद्धि हुई, हालांकि उपयोगिता क्षेत्र में अधिक मंदी का अनुभव किया गया क्योंकि बिजली और पानी की आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवाओं को राष्ट्रीय लॉकडाउन होने के बावजूद भी सही स्तर पर बनाए रखा गया था। जीवीए में उद्योग की हिस्सेदारी अब 28.2 प्रतिशत होने का अनुमान है (तालिका 2)।

तालिका 2: जीवीए (सकल मूल्य वर्धन, प्रचलित भावों पर) में क्षेत्रों का हिस्सा (प्रतिशत)

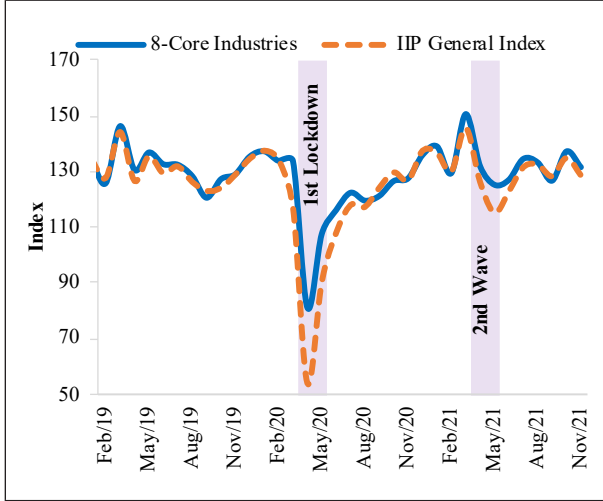
क्षेत्र	2019-20 (1 सं.अ.)	2020-21 (अ.अ.)	2021-22 (1 अग्रिम अ.)
कृषि और संबद्ध क्षेत्र	18.4	20.2	18.8
उद्योग	26.7	25.9	28.2
खनन और उत्खनन	1.9	1.6	2.3
विनिर्माण	14.7	14.4	15.4
बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	2.6	2.7	2.5
निर्माण	7.4	7.2	8.0
सेवाएं	55.0	53.9	53.0
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं	18.9	16.4	16.9
वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं	21.2	22.1	20.9
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	14.9	15.4	15.2
मूल कीमत पर जीवीए	100.0	100.0	100.0

स्रोत: एनएसओ

नोट: सं.अ.: संशोधित अनुमान, अ.अ.: अर्न्तम अनुमान, अग्रिम अ.: अग्रिम अनुमान

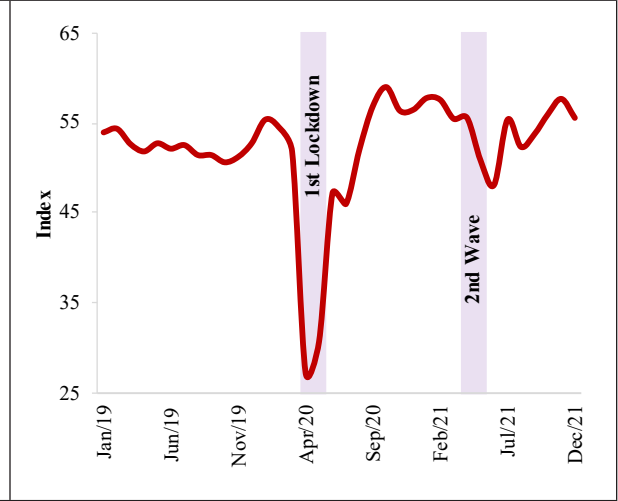
1.6 जनवरी, 2021 से व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले क्रय प्रबंधकों का सूचकांक-विनिर्माण एक महीने को छोड़कर विस्तार क्षेत्र (यानी 50 से अधिक) में बना हुआ है, जबकि दूसरी लहर में आर्थिक गतिविधि धीमी हो गई थी (चित्र 8)। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) और मुख्य उद्योग सूचकांक दोनों में एक समान चलन देखा गया है और ये सूचकांक नवंबर, 2021 में, 2019 के इसी महीने के अपने पूर्व-महामारी स्तर से आगे निकल गए (चित्र 7)।

चित्र 7: औद्योगिक उत्पादन



स्रोत: एमओएसपीआई, डीपीआईआईटी

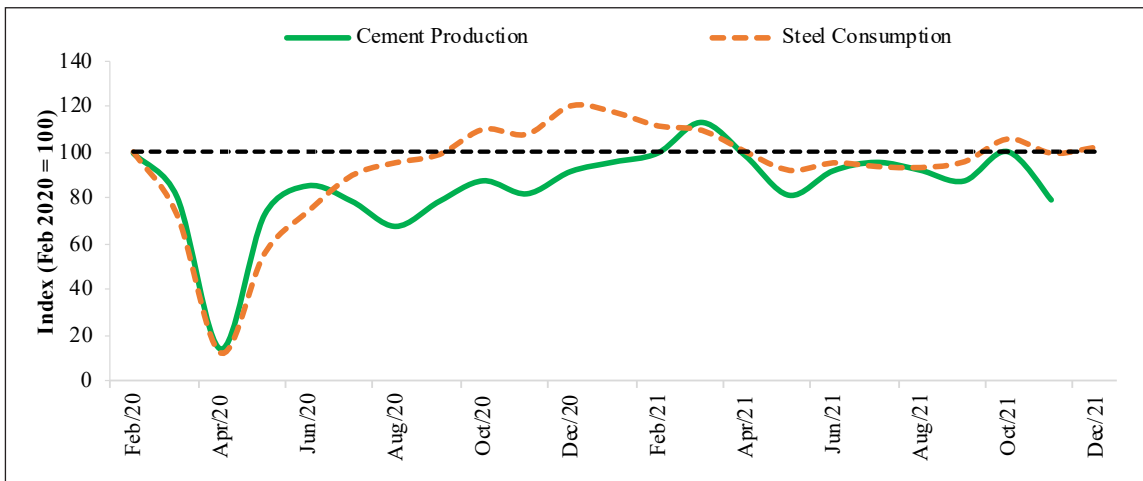
चित्र 8: पीएमआई विनिर्माण



स्रोत: आईएचएस मार्किट

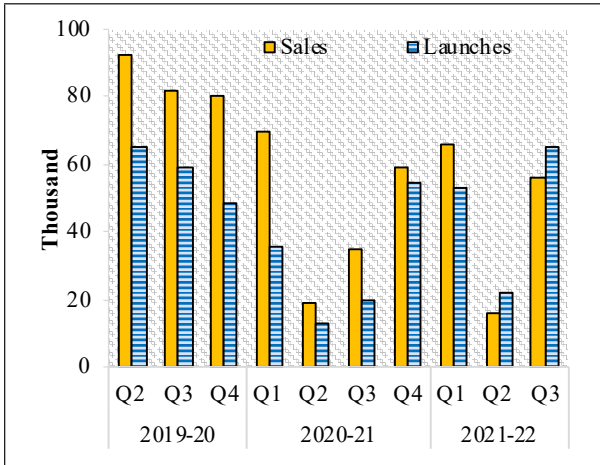
1.7 अवसंरचना पर सरकार द्वारा बढ़ते पूंजीगत व्यय और आवास चक्र में वृद्धि के कारण निर्माण क्षेत्र पुनर्जीवित हुआ है। इससे स्टील और सीमेंट की खपत और उत्पादन को पूर्व-कोविड स्तर (चित्र 9) पर वापस आ सका है। आरबीआई और प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े बिक्री, कीमतों और नई योजना (चित्र 10 और 11) में वृद्धि के संदर्भ में 2021 में भारतीय आवासीय बाजार में महत्वपूर्ण पुनरुद्धार दर्शाते हैं।

चित्र 9: निर्माण क्षेत्र संकेतक

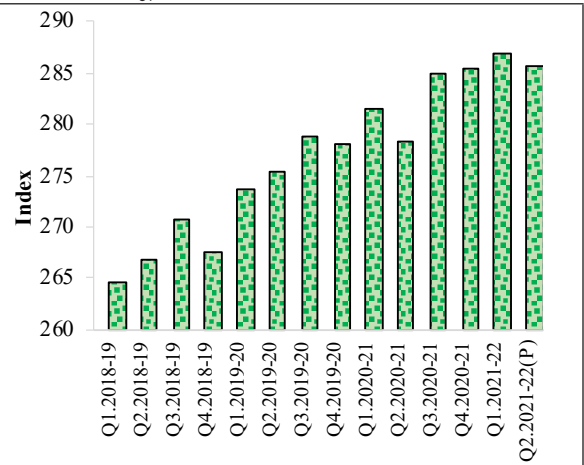


स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति; और आर्थिक सलाहकार कार्यालय, डीपीआईआईटी

चित्र 10: शीर्षस्थ 8 शहरों में आवास बिक्री और नई योजनाएँ



चित्र 11: आरबीआई आवास मूल्य सूचकांक: अखिल भारतीय

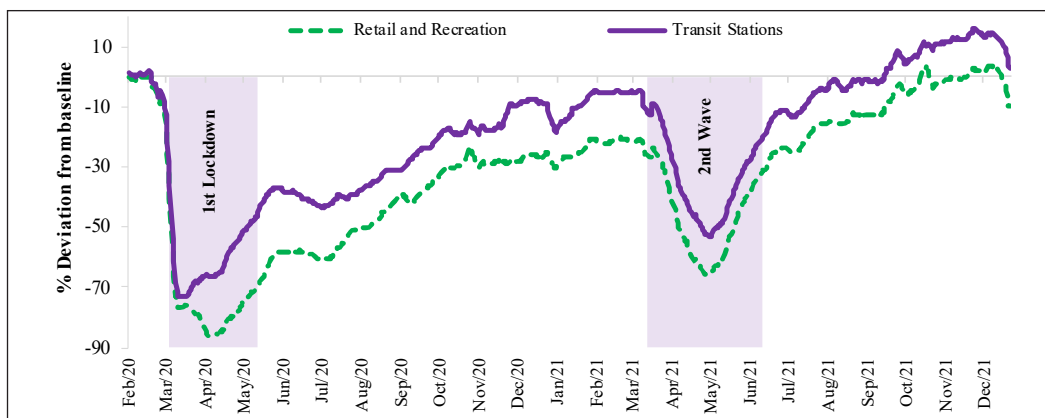


स्रोत: एनारॉक, प्रोपटीगर, आरबीआई

1.8 भारतीय अर्थव्यवस्था में आधे से अधिक सेवा क्षेत्र का हिस्सा है, और यह कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों से सबसे अधिक प्रभावित हुआ, विशेष रूप से वे गतिविधियां जिनमें मानव संपर्क की आवश्यकता होती है। हालांकि, समग्र क्षेत्र में पहले 2020-21 में 8.4 प्रतिशत का संकुचन हुआ और फिर 2021-22 में 8.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, परंतु यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विभिन्न उप-क्षेत्रों द्वारा प्रदर्शन में भारी अंतर है। वित्त/रियल एस्टेट और लोक प्रशासन क्षेत्र दोनों अब पूर्व-कोविड स्तरों से काफी अच्छे हैं। हालांकि, यात्रा, व्यापार और होटल जैसे क्षेत्र अभी पूरी तरह से बहाल नहीं हुए हैं। यह पुनः ध्यान दिया जाना चाहिए कि महामारी की लहरों की बार-बार आने-जाने की प्रकृति इन उप-क्षेत्रों की गति पकड़ने को कठिन बना देती है।

1.9 संपर्क-संवेदनशील सेवाओं पर अभी भी कोविड का प्रभाव होने के बावजूद, अगस्त 2021 (चित्र 13) से क्रय प्रबंधकों के सूचकांक-सेवाओं (पीएमआई सर्विसिस) में काफी सुधार हुआ है। इस संदर्भ में, वास्तविक समय के रुझानों का पता लगाने के लिए उच्च आवृत्ति संकेतकों के नए रूपों की भूमिका पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, खुदरा और मनोरंजन के लिए गूगल गतिशीलता संकेतक (अर्थात्, रेस्तरां, कैफे, शॉपिंग सेंटर, आदि) और ट्रांजिट स्टेशन गतिशीलता संकेतक (सार्वजनिक परिवहन केंद्र जैसे सबवे, बस और ट्रेन स्टेशन), जोकि महामारीपूर्व स्तरों की तुलना में प्रतिशत विचलन को मापते हैं, को देखें। इन संकेतकों ने दिसंबर 2021 में (ओमीक्रोन वेरिएंट संबंधी प्रतिबंध से पहले) महामारीपूर्व स्तर को पार कर लिया था (चित्र 12)। इसी तरह, होटल अधिभोग दर में काफी सुधार हुआ है, जो अप्रैल 2021 में 30-32 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर 2021 में 56-58 प्रतिशत तक पहुंच गया है (चित्र 14)।

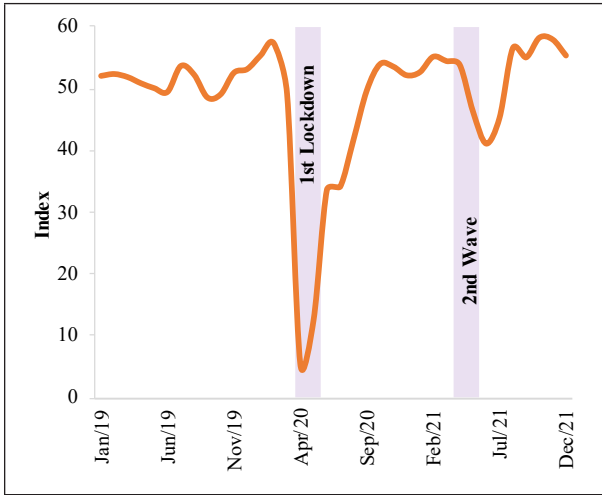
चित्र 12: गतिशीलता में रुझान



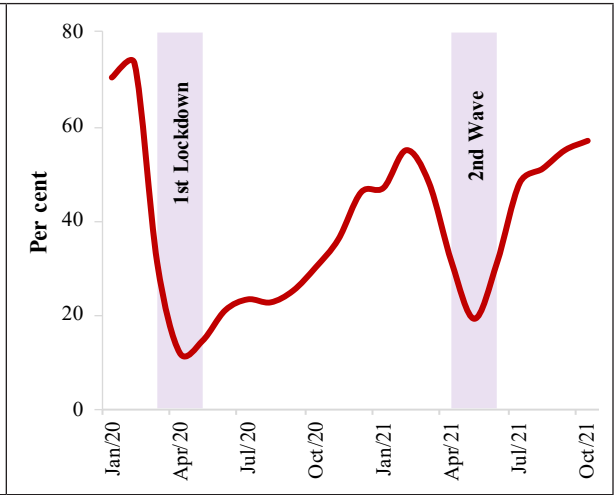
स्रोत: गूगल मोबिलिटी

नोट: बेसलाइन जनवरी-फरवरी, 2020 स्तर से मेल खाती है

चित्र 13: पीएमआई सेवाएं



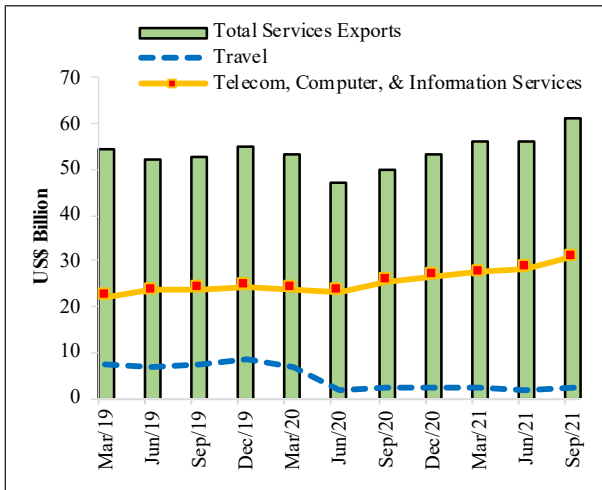
चित्र 14: होटल अधिभोग दर



स्रोत: आईएचएस मार्किट, एनारॉक

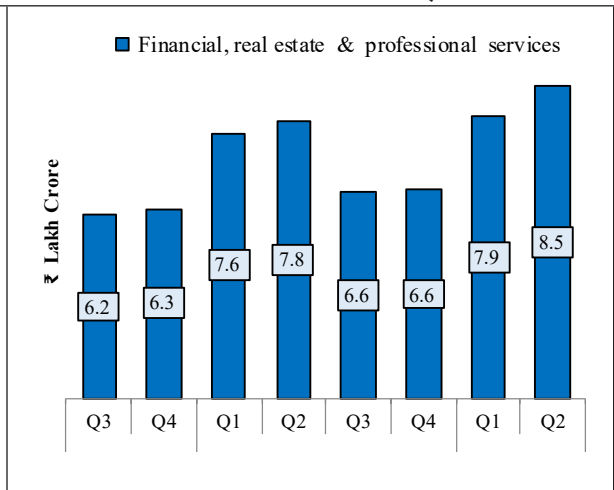
1.10 कार्यालय संबंधी काम, शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं में दूरस्थ इंटरफेस की बढ़ती प्राथमिकता के चलते, संपर्क-आधारित सेवाओं के विपरीत, दूरस्थ सक्षम सेवाओं का जीवीए (सकल मूल्य वर्धन) में हिस्सा बढ़ा है। सॉफ्टवेयर और आईटी द्वारा संचालित सेवाओं के निर्यात में उछाल आया है, भले ही पर्यटन से आय में तेजी से गिरावट आई है (चित्र 15 और 16 देखें)।

चित्र 15: सेवा निर्यात में तिमाही रुझान



स्रोत: आरबीआई, एनएसओ

चित्र 16: दूरस्थ सक्षम सेवाओं का वास्तविक जीवीए



मांग का रुझान

1.11 निजी खपत को छोड़कर, नवीनतम अग्रिम अनुमान 2021-22 मांग के सभी घटकों में पूर्ण वापसी आने का संकेत देते हैं। जब महामारीपूर्व स्तरों की तुलना की जाए, तो सरकारी खपत और सकल अचल पूंजी निर्माण के बाद निर्यात में बहाली सबसे अधिक है, तथापि, आयातों में समान रूप से काफी सुधार देखा गया (तालिका 3 और 4)।

तालिका 3: सकल घरेलू उत्पाद और उसके घटकों की मांग में वार्षिक वास्तविक वृद्धि (प्रतिशत)

घटक	2019-20 (पहला सं.अ.)	2020-21 (अ.अ.)	2021-22 (पहला अग्रिम अ.)	2019-20 से बहाली की %
कुल खपत	5.9	-7.3	7.0	99.2
सरकारी खपत	7.9	2.9	7.6	110.7
निजी खपत	5.5	-9.1	6.9	97.1
कुल स्थायी पूंजी निर्माण	5.4	-10.8	15.0	102.6
निर्यात	-3.3	-4.7	16.5	111.1
आयात	-0.8	-13.6	29.4	111.8
सकल घरेलू उत्पाद	4.0	-7.3	9.2	101.3

स्रोत: एनएसओ

नोट: सं.अ. - संशोधित अनुमान, अ.अ. - अर्न्तम अनुमान, अग्रिम अ. - अग्रिम अनुमान

तालिका 4: सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भावों पर) में क्षेत्रों का हिस्सा (प्रतिशत)

क्षेत्र	2019-20 (1 सं.अ.)	2020-21 (अ.अ.)	2021-22 (1 अग्रिम अ.)
कुल खपत	71.7	71.1	69.7
सरकारी खपत	11.2	12.5	12.2
निजी खपत	60.5	58.6	57.5
कुल निश्चित पूंजी निर्माण	28.8	27.1	29.6
शुद्ध निर्यात	-2.5	-0.5	-3.0
निर्यात	18.4	18.7	20.1
आयात	21.0	19.2	23.1
सकल घरेलू उत्पाद	100.0	100.0	100.0

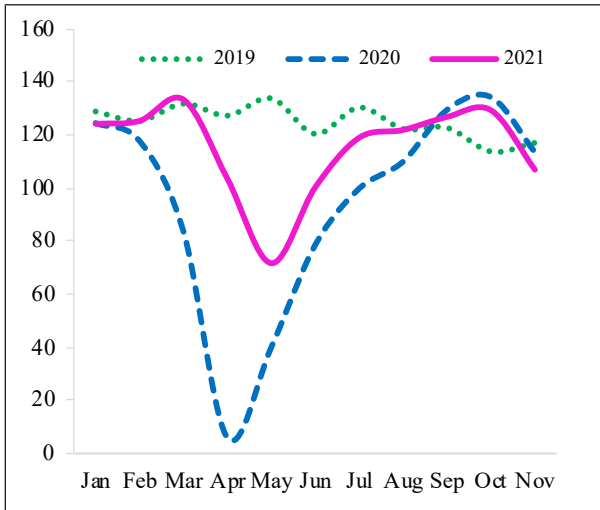
स्रोत: एनएसओ

नोट: सं.अ.: संशोधित अनुमान, अ.अ.: अर्न्तम अनुमान, अग्रिम अ.: अग्रिम अनुमान

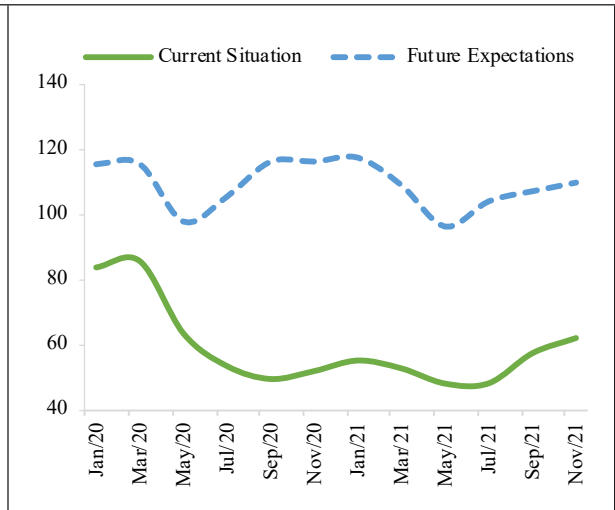
उपभोग

1.12 2021-22 में कुल खपत में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जिसमें सरकारी खपत का पिछले वर्ष की तरह सबसे बड़ा योगदान है (तालिका 3)। सरकार की खपत में महामारीपूर्व के स्तर को पार करते हुए 7.6 प्रतिशत की भारी वृद्धि का अनुमान है। निजी खपत में भी उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है, जो कि महामारीपूर्व उत्पादन स्तर की तुलना में 97 प्रतिशत का सुधार होगा। उसमें आईआईपी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (उपभोक्ता के लिए टिकाऊ वस्तुएं) (चित्र 17) जैसे एचएफआई में तेज वापसी से मदद मिली है। हालांकि, वाहन पंजीकरण में हालिया गिरावट खपत मांग की कमी के बजाय सेमी-कंडक्टर चिप्स की कमी के कारण आपूर्ति में कमी को दर्शाती है। इसे वैश्विक आपूर्ति में व्यवधानों से संबंधित बॉक्स 2 में दर्शाया गया है। इसके अलावा, वर्तमान स्थिति और भविष्य की अपेक्षाओं दोनों पर आरबीआई के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के परिणाम उपभोक्ता मनोभावों में निरंतर वृद्धि का संकेत देते हैं (चित्र 18)। इसके अलावा उपभोक्ता मनोभावों में तेजी का संकेत डिजिटल लेनदेन में तेज वृद्धि है, विशेष रूप से यूपीआई भुगतानों में महामारी प्रेरित संपर्क रहित भुगतान के कारण। टीकाकरण तेजी से होने और आर्थिक गतिविधियों के तेजी से सामान्य होने के कारण निजी खपत में काफी सुधार देखने की संभावना है।

चित्र 17: आईआईपी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु सूचकांक



चित्र 18: आरबीआई का उपभोक्ता विश्वास सूचकांक

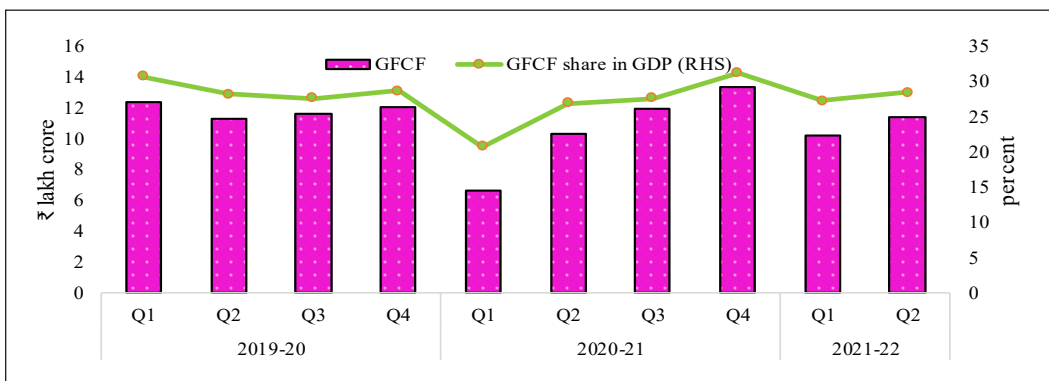


स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी, आरबीआई

निवेश

1.13 सकल अचल पूंजी निर्माण अर्थात् निवेश में 2021-22 में 15 प्रतिशत की भारी वृद्धि दिखने और महामारीपूर्व स्तर में पूर्ण रूप से वापस आने की उम्मीद है। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और अवसंरचना में खर्च के माध्यम से विकास के तीव्र चक्र की तेजी लाने से संबंधित सरकार की नीति के कारण अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण में वृद्धि हुई है जिससे 2021-22 में निवेश - जीडीपी अनुपात बढ़कर लगभग 29.6 प्रतिशत हो गया है, जो सात वर्षों में सबसे अधिक है (चित्र 19)।

चित्र 19: सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ)



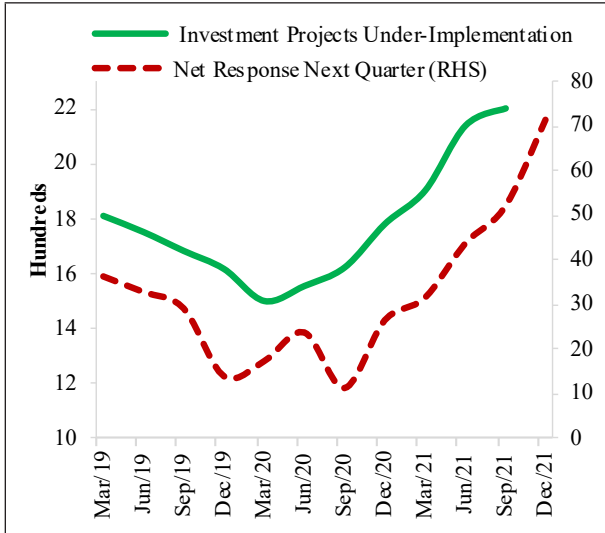
स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई

नोट: स्थिर (2011-12 की कीमतों) पर पूर्ण आंकड़े, मौजूदा कीमतों के अनुसार शेयर

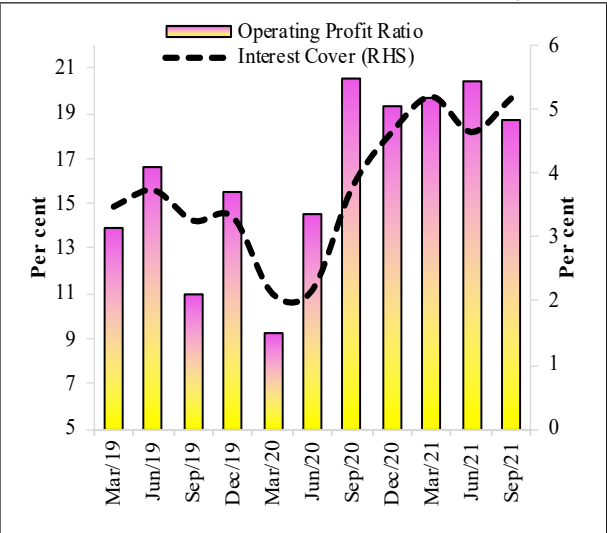
1.14 जबकि निजी निवेश की वसूली अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है, ऐसे कई संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि भारत मजबूत निवेश के लिए तैयार है। विनिर्माण क्षेत्र में कार्यान्वयन के तहत निजी निवेश परियोजनाओं की संख्या वर्ष के दौरान बढ़ रही है (चित्र 20)। हाल की तिमाहियों में कंपनियों के रिकॉर्ड मुनाफा कमाने और जोखिम पूंजी जुटाने से निजी निवेश में तेजी आने का संकेत मिलता है (चित्र 21)। एक मजबूत और साफ-सुथरा बैंकिंग क्षेत्र निजी निवेश को पर्याप्त रूप से समर्थन देने के लिए तैयार है। निजी खपत के स्तर में अपेक्षित वृद्धि क्षमता उपयोग को बढ़ावा देगी, जिससे निजी निवेश गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। आरबीआई के

नवीनतम औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण के परिणाम आगामी तिमाहियों में निवेशकों की बढ़ती आशावाद और उत्पादन में विस्तार का संकेत देते हैं।

चित्र 20: विनिर्माण में निवेशक भावना



चित्र 21: गैर-वित्तीय क्षेत्र लाभप्रदता अनुपात



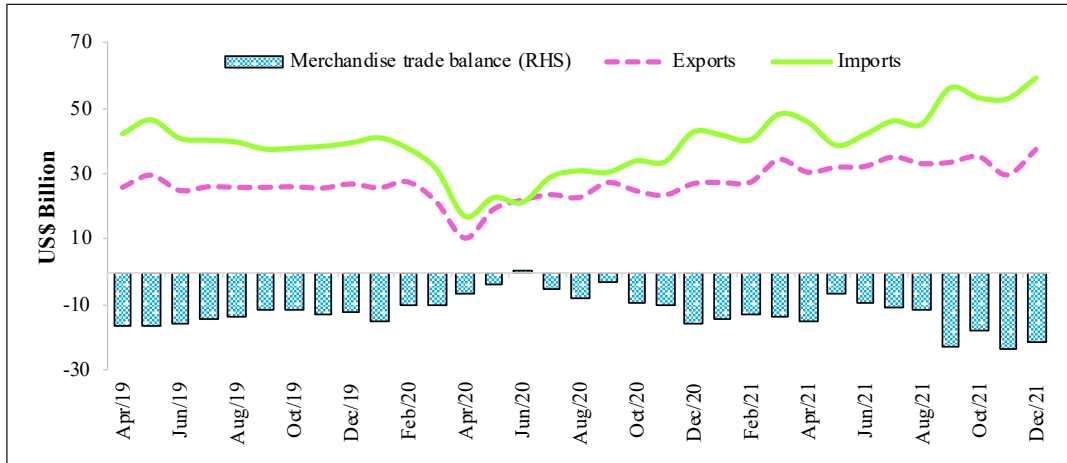
स्रोत: सीएमआईआई कैपेक्स डाटाबेस, आरबीआई इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे, प्रोवेस डाटाबेस

निर्यात और आयात

1.15 भारत का माल और सेवाओं दोनों का निर्यात 2021-22 में अब तक असाधारण रूप से मजबूत रहा है। वैश्विक आपूर्ति बाधाओं जैसे कि शिपिंग जहाजों का कम परिचालन, स्वेज नहर की रुकावट और चीन का बंदरगाह शहर आदि में कोविड-19 के प्रकोप जैसी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं से उत्पन्न व्यापार लागत में वृद्धि के बावजूद, व्यापारिक निर्यात 2021-22 में लगातार आठ महीनों के लिए 30 बिलियन अमरीकी डॉलर से ऊपर रहा है (चित्र 22)। समवर्ती रूप से, पेशेवर और प्रबंधन परामर्श सेवाओं, श्रव्य दृश्य और संबंधित सेवाओं, माल परिवहन सेवाओं, दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं द्वारा संचालित शुद्ध सेवाओं के निर्यात में भी तेजी से वृद्धि हुई है (चित्र 23)। मांग के नजरिए से, भारत का कुल निर्यात 2021-22 में 16.5 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है जो महामारी से पहले के स्तर को पार कर जाएगा। घरेलू मांग में सुधार और आयातित कच्चे तेल और धातुओं की कीमत में निरंतर वृद्धि के साथ आयात में भी मजबूती आई। 2021-22 में आयात में 29.4 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो कि पूर्व-महामारी के स्तर को पार कर गया है।

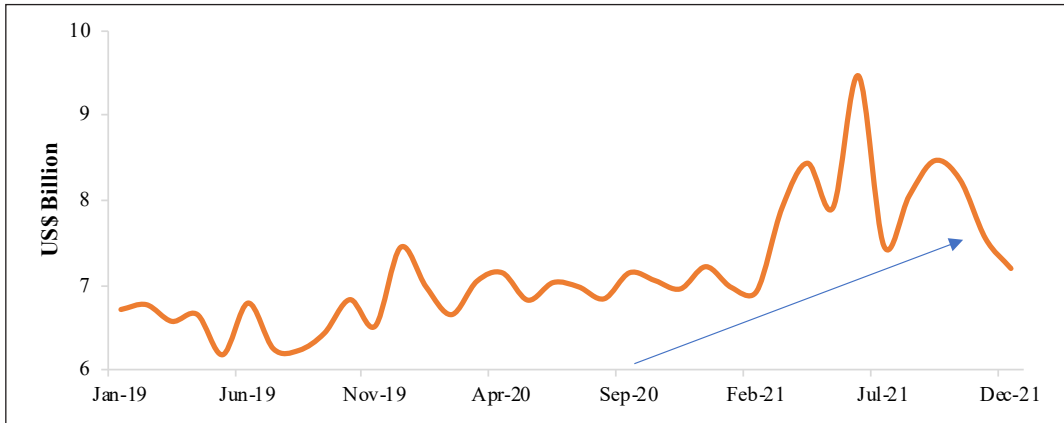
1.16 परिणामस्वरूप, भारत का निवल निर्यात 2021-22 की पहली छमाही में नकारात्मक हो गया है, जबकि 2020-21 की इसी अवधि में अधिशेष की तुलना में चालू खाते में पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 0.2 प्रतिशत का मामूली घाटा दर्ज किया गया है (चित्र 24)। हालांकि, विदेशी निवेश के निरंतर अंतर्वाह के रूप में मजबूत पूंजी प्रवाह मामूली चालू खाता घाटे को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। वैश्विक पण्य कीमतों में वृद्धि, उच्च घरेलू मांग को बढ़ावा देने वाली वास्तविक आर्थिक गतिविधि में पुनरुद्धार और पूंजी प्रवाह के आसपास बढ़ती अनिश्चितता वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान चालू खाता घाटे को और बढ़ा सकती है। हालांकि, यह प्रबंधनीय सीमा के भीतर होने की उम्मीद है।

चित्र 22: पण्य व्यापार



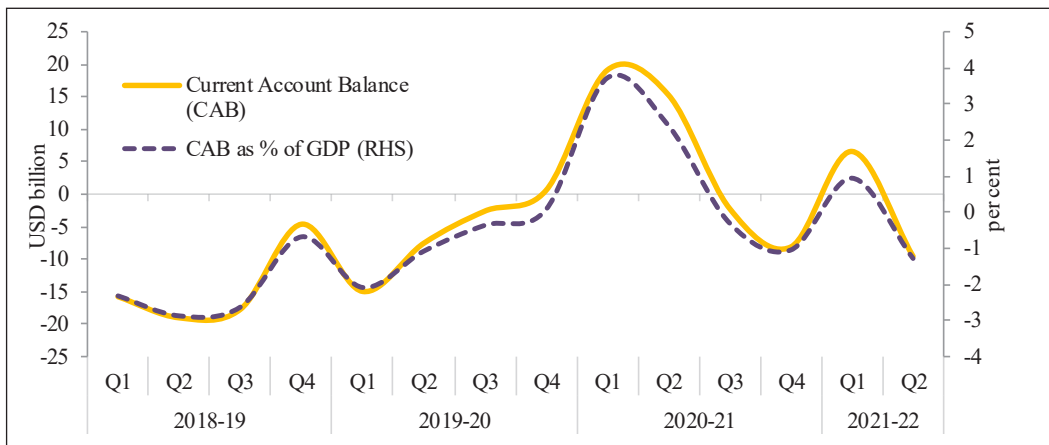
स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

चित्र 23: सेवाओं में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नेट



स्रोत: आरबीआई

चित्र 24: भारत का चालू खाता शेष



स्रोत: आरबीआई

बारबेल रणनीति, सुरक्षा जाल और चुस्तदुरुस्त प्रतिक्रिया

1.17 परिवर्तनशील वायरस की नई लहरों, यात्रा प्रतिबंध, आपूर्ति-श्रृंखला व्यवधान और हाल ही में, वैश्विक मुद्रास्फीति के चलते पिछले दो साल दुनिया भर में नीति-निर्माण के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण रहे हैं। इन सभी अनिश्चितताओं का सामना करते हुए, भारत सरकार ने "बारबेल स्ट्रैटेजी" का विकल्प चुना, जिसमें समाज/व्यवसाय के कमजोर वर्गों पर प्रभाव को कम करने के लिए सुरक्षा-जाल का गठन किया गया, जिसमें सूचना के बेज़ियन अपडेट के आधार पर एक लचीली नीतिगत प्रतिक्रिया थी। जैसा कि पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है, यह वित्तीय बाजारों में इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य रणनीति है जिसका उपयोग दो अलग-अलग प्रतिक्रियाओं को मिलाकर अत्यधिक अनिश्चितता से निपटने के लिए किया जाता है। जैसा कि कुछ पाठकों ने अनुमान लगाया होगा, इस रणनीति का पुनरावृत्ति चरण एजायल कार्यप्रणाली के समान है जो फीडबैक-लूप (प्रतिक्रिया-पाश) और रीयल-टाइम अपडेट (वास्तविक काल समायोजन) का उपयोग करता है।

1.18 एजायल कार्यप्रणाली अच्छी तरह से स्थापित एक बौद्धिक ढांचा है जो परियोजना प्रबंधन और प्रौद्योगिकी विकास जैसे क्षेत्रों में काफी उपयोग किया जाता है। अनिश्चित वातावरण में, सक्रिय रूपरेखा (चुस्तदुरुस्त फ्रेमवर्क) छोटे पुनरावृत्तियों में परिणामों का आकलन करके और लगातार वृद्धिशील रूप से समायोजित करके प्रतिक्रिया करती है। यहां सक्रिय (चुस्तदुरुस्त) को "वाटरफॉल" ढांचे से अलग करना महत्वपूर्ण है जो भारत और दुनिया के अधिकांश हिस्सों में नीति तैयार करने का पारंपरिक तरीका रहा है। वाटरफॉल दृष्टिकोण में समस्या का एक विस्तृत, प्रारंभिक मूल्यांकन शामिल है, जिसके बाद कार्यान्वयन के लिए एक दृढ़ अग्रिम योजना बनाई जाती है। यह पद्धति इस आधार पर काम करती है कि सभी आवश्यकताओं को शुरुआत में समझा जा सकता है और इसलिए यह कार्रवाई के निश्चित मार्ग के लिए पूर्व-प्रतिबद्ध है। यही सोच पंचवर्षीय आर्थिक योजनाओं और दृढ़ शहरी मास्टर-प्लानों में परिलक्षित होती है।

1.19 जबकि फीडबैक-लूप आधारित नीति-निर्माण के कुछ रूप हमेशा संभव थे, यह विशेष रूप से ऐसे समय में प्रभावी है जब हमारे पास रीयल-टाइम डेटा का संग्रह है। पिछले दो वर्षों में, सरकार ने सरकारी विभागों/एजेंसियों के साथ-साथ निजी संस्थानों से अनेक उच्च आवृत्ति संकेतकों (एचएफआई) का लाभ उठाया, जो निरंतर निगरानी और पुनरावृत्त अनुकूलन को सक्षम बनाता है। इस तरह की सूचनाओं में जीएसटी संग्रह, बिजली की खपत, गतिशीलता संकेतक, डिजिटल भुगतान, उपग्रह तस्वीरें, जहाजी माल आवाजाही, राजमार्ग टोल संग्रह आदि शामिल हैं। इन एचएफआई ने नीति निर्माताओं को वाटरफॉल ढांचे की पूर्व-निर्धारित प्रतिक्रियाओं पर भरोसा करने के बजाय एक विकसित स्थिति के लिए अपनी प्रतिक्रियाओं को तैयार करने में मदद की।

1.20 ध्यान दें कि सक्रिय एजायल कार्यप्रणाली का लचीलापन प्रतिक्रियात्मकता में सुधार करता है और विकास में सहायता करता है, लेकिन यह परिणामों की भविष्यवाणी करने का प्रयास नहीं करता है। यही कारण है कि बारबेल रणनीति के दूसरे चरण की भी आवश्यकता है। यह सुरक्षा जाल प्रदान करके अप्रत्याशित नकारात्मक परिणामों को हल्का करने का काम करता है। यह बताता है कि 2020-21 में सरकार के शुरुआती उपाय ज्यादातर गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के लिए आपातकालीन नकदी सहायता प्रदान करने और दिवाला और दिवालियापन संहिता को स्थगित करने के बारे में थे। एक बार ये लागू हो जाने के बाद, सरकार ने विशिष्ट चुनौतियों पर लक्षित पैकेजों की नियमित रूप से घोषणा करते हुए आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। इसकी तुलना कई अन्य देशों द्वारा अग्रिम राहत पैकेज की घोषणा के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण से करें। निम्नलिखित चर्चा अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा-जाल उपायों का एक सिंहावलोकन प्रदान करती है, जबकि अध्याय 2 इस बात का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है कि पूंजीगत व्यय और आपूर्ति-पक्ष संबंधी उपायों, जैसे उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, से समय के साथ राजकोषीय मिश्रण कैसे बदल गया।

कमजोर वर्गों को सहारा देने के लिए सुरक्षा जाल का उपयोग



1.21 'सदी में एक बार होने वाली' महामारी से जुड़ी अत्यधिक अनिश्चितता को पहचानते हुए सरकार ने आपातकालीन सहायता और आर्थिक नीति कार्यों के सावधानीपूर्वक मिश्रण का विकल्प चुना ताकि महामारी




से प्रेरित झटकों के खिलाफ एक सहारा प्रदान किया जा सके, और लचीले ढंग से एक विकसित स्थिति को अपनाया जा सके।



1.22 2020 की शुरुआत में, जब दुनिया भर में महामारी की पहली लहर चल रही थी, सरकार ने आपातकालीन नीतिगत कार्रवाइयों के माध्यम से लोगों की जान बचाने पर ध्यान केंद्रित किया। इन कार्रवाइयों में से पहली कार्रवाई मार्च 2020 में एक कड़े लॉकडाउन को लागू करना थी जबकि मामले अभी भी कम थे। इसने परीक्षण के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, क्वारंटाइन अर्थात् संगरोध सुविधाएं बनाने आदि के लिए आवश्यक समय प्रदान किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने कोविड-19 वायरस, इसके लक्षण और यह कैसे फैलता है, इसको समझने का आवश्यक समय दिया।


1.23 सरकार ने माना कि लॉकडाउन और क्वारंटाइन आर्थिक गतिविधियों को बाधित करते हैं। इसलिए, विश्व के सबसे बड़े मुफ्त भोजन कार्यक्रम, प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण और छोटे व्यवसायों के लिए राहत उपायों (तालिका 5 में विवरण) सहित आर्थिक सुरक्षा तंत्र को जल्दी से स्थापित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने साथ-साथ अर्थव्यवस्था को मौद्रिक सहायता प्रदान की। इनमें से कई सुरक्षा जाल प्रावधान दूसरी लहर के दौरान जारी रहे और आवश्यकतानुसार आगे बढ़ाए गए। इसके साथ टीकाकरण कार्यक्रम में तीव्र बढ़ोतरी की गई जैसा कि अध्याय में आगे चर्चित है।

तालिका 5: कोविड-19 के दौरान आपदा को रोकने के लिए गठित सुरक्षा जाल के प्रमुख उपाय

 <p>नकद हस्तांतरण</p>	महिला जन धन खाताधारकों को ₹ 500/माह 3 महीने के लिए	<ul style="list-style-type: none"> 20.64 करोड़ महिला लाभार्थियों को ₹ 30,944 करोड़ जारी किए गए
	कमजोर वर्ग (विधवा, दिव्यांग, बुजुर्ग) को ₹ 1000	<ul style="list-style-type: none"> 2.82 करोड़ लाभार्थियों को कवर करते हुए ₹ 2814 करोड़ जारी किए गए
	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) - ब 6000/- प्रति वर्ष तीन किस्तों में	<ul style="list-style-type: none"> फरवरी 2019 से 1.1.2022 तक 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को ₹ 1.8 लाख करोड़ हस्तांतरित किए गए, यानी, कोविड-19 के समय से 6 किश्तें खाद्य सुरक्षा
 <p>खाद्य सुरक्षा</p>	प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना - 80 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लाभार्थियों को अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न @ 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह, नियमित मासिक एनएफएसए खाद्यान्न के अलावा	<ul style="list-style-type: none"> मार्च 2020 में शुरू किया गया, चरण-V - के तहत मार्च 2022 तक बढ़ाया गया मार्च-2020 से नवंबर-2021 तक, खाद्य सब्सिडी में ₹ 2.07 लाख करोड़ के बराबर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित 600 एलएमटी खाद्यान्न
	वन नेशन वन राशन कार्ड पारगमन में लोगों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए पीडीएस लाभ सुनिश्चित करने के लिए।	<ul style="list-style-type: none"> 94.3 प्रतिशत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की आबादी को कवर करते हुए अगस्त 2021 तक 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सक्षम, 1.4.2020 और 30.9.2021 के बीच 24.32 करोड़ रुपये का पोर्टेबिलिटी लेनदेन किए गए
	उज्ज्वला के तहत रसोई गैस सिलेंडर	<ul style="list-style-type: none"> अप्रैल से जून 2020 के लिए 8 करोड़ लाभार्थियों को 3 मुफ्त सिलेंडर। उज्ज्वला 2.0 के तहत पहला रिफिल और हॉटप्लेट मुफ्त (शुरुआत 10.8.2021) सरल प्रक्रियाओं के साथ

<p style="text-align: center;">रोजगार</p> 	<p>प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएम-जीकेआरए के तहत) बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों में प्रवासी श्रमिकों को तत्काल रोजगार और आजीविका के अवसरों के लिए</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 27.07.21 को ₹ 39,293 करोड़ के व्यय के साथ 50.8 करोड़ मानव-दिवस रोजगार सृजित किए
	<p>महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2020-21 में 389.2 करोड़ कार्य दिवस सृजित करने वाले 11.2 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया। ₹ 1,11,171 करोड़ की धनराशि जारी ● 2021-22 (25.11.2021 तक): 240.4 करोड़ कार्य दिवस पैदा करने वाले 8.85 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया। ₹ 68,233 करोड़ की धनराशि जारी।
	<p>मनरेगा मजदूरी में 2019-20 की मजदूरी दर से ₹ 20 की वृद्धि</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए मजदूरी दर 1.4.2020 से संशोधित
	<p>₹ 15000/- से कम आय वाले 90 प्रतिशत कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत 6 महीने के लिए 12 प्रतिशत नियोक्ता और 12 प्रतिशत कर्मचारी का अंशदान</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● कोविड के बाद ईपीएफओ पंजीकृत प्रतिष्ठानों में संरक्षित रोजगार
	<p>आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) नियोक्ताओं के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए और उन्हें ईपीएफओ द्वारा कार्यान्वित अधिक श्रमिकों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● दिनांक 20.11.2021 तक 1.15 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 39.43 लाख हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया
<p style="text-align: center;">आवास</p> 	<p>प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2020-21: 33.99 लाख घरों का निर्माण पूरा ● 2021-22 (25.11.21 तक): 26.20 लाख घरों का निर्माण पूरा
	<p>प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2020-21: 14.56 लाख घरों का निर्माण पूरा ● 2021-22: 4.49 लाख घरों का निर्माण पूरा (दिसंबर-21 तक)
<p style="text-align: center;">कौशल विकास</p> 	<p>दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) - ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम डीडीयू-जीकेवाई</p>	<p>डीडीयू-जीकेवाई</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2020-21: 38,289 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया और 49,563 अभ्यर्थियों को नौकरी पर रखा गया ● 2021-22 (अक्टूबर*21 तक): 14,568 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया और 21,369 उम्मीदवारों को नौकरी दी गई आरएसईटीआई ● 2020-21: 207712 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया और 138537 अभ्यर्थियों का निपटारा किया गया

		<ul style="list-style-type: none"> ● 2021-22 (30.10.2021 तक): 114640 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया और 61546 अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया
	प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत 6 राज्यों को सम्मिलित करने वाले प्रवासी कामगारों का नवीन कौशल और उच्च कौशल	<ul style="list-style-type: none"> ● 21.11.2021 तक 1.24 लाख प्रवासी श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया
<p>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग</p> 	आरबीआई द्वारा सभी सावधि ऋणों के लिए 1.3.2020 से 31.8.2020 तक 6 महीने का अधि स्थगन और ब्याज का आस्थगन मोहलत	<ul style="list-style-type: none"> ● 31.08.2020 तक एमएसएमई उधारकर्ताओं के 77.2 प्रतिशत और एससीबी के 43.7 प्रतिशत व्यक्तिगत उधारकर्ताओं द्वारा लाभ उठाया गया
	एमएसएमई डिफॉल्ट ऋणों का पुनर्गठन - अगस्त 2020 और मई 2021 आरबीआई की योजनाएं	<ul style="list-style-type: none"> ● एससीबी द्वारा 12.11.2021 तक ₹ 78,591 करोड़ का कुल पुनर्गठित निवेश सूची ● पीएसबी द्वारा 9.8 लाख एमएसएमई खातों में ब 58,524 करोड़ की राशि का समाधान/पुनर्गठन
	आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना - कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए व्यवसायों (विशेष रूप से एमएसएमई) को ₹ 4.5 लाख करोड़ तक के अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए 100 प्रतिशत गारंटी	<ul style="list-style-type: none"> ● 19.11.2021 तक 5.45 करोड़ कर्मचारियों को प्रभावित करते हुए, 95.2 लाख उधारकर्ताओं को ₹ 2.28 लाख करोड़ वितरित किए गए ● एमएसएमई को वितरित गारंटी राशि का 66 प्रतिशत ● 31.03.2022 तक बढ़ाया गया
	एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस)	<p>क्रेडिट गारंटी / मार्जिन मनी प्रदान की गई</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2020-21: ₹ 36,899 करोड़ ● 2021-22: ₹ 22,959 करोड़ (30.11.2021 तक)
<p>ऋण</p> 	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत कॉरपोरेट दिवाला प्रक्रिया शुरू करने पर 1 साल के लिए रोक, और न्यूनतम सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने के लिए	<ul style="list-style-type: none"> ● 25.3.2020 से 24.3.2021 के दौरान भुगतान में चूक माफ
	31.3.2022 तक आरबीआई द्वारा आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ₹ 50,000 करोड़ की अवधि नकदी सुविधा	<ul style="list-style-type: none"> ● 31.04.2021 को घोषित किया गया
	सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) को उधार देने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना	<ul style="list-style-type: none"> ● शुरूआत होने के 75 दिनों (28.6.2021) में पूरी तरह से उपयोग, ₹ 7500 करोड़ स्वीकृत
	एमएसएमई और व्यक्तियों को नए ऋण देने के लिए एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआई के लिए ₹ 45,000 करोड़ की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0	<ul style="list-style-type: none"> ● 25.9.2020 तक, ₹ 25,505 करोड़ के निवेश सूची को बैंकों द्वारा अनुमोदित किया गया। ● पीएसबी: ₹ 27,794 करोड़ का निवेश सूची 4.12.2020 तक खरीदा गया
	31.10.2021 तक उपलब्ध लघु वित्त बैंकों के लिए विशेष दीर्घकालिक रेपो संचालन	<ul style="list-style-type: none"> ● 31.04.2021 को घोषित किया गया

	लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) द्वारा एमएफआई को ऋण देने के लिए 31.3.2022 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के रूप में वर्गीकृत किया जाना है।	<ul style="list-style-type: none"> ● 31.04.2021 को घोषित किया गया
	नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए ब 30,000 करोड़ अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी निधि	<ul style="list-style-type: none"> ● 25.9.2020 तक ब 25,000 करोड़ का वितरण शेष ₹ 5,000 करोड़ छोटे एनबीएफसी और ● एनबीएफसी-एमएफआई के लिए आरबीआई द्वारा नाबार्ड को आवंटित किया गया।
	राष्ट्रव्यापी क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम 16.10.2021 को शुरू किया गया	<ul style="list-style-type: none"> ● 26.11.2021 तक ₹ 96,063 करोड़ ऋण स्वीकृत
	किसान क्रेडिट कार्ड विशेष अभियान- 2.5 करोड़ किसानों को ₹ 2 लाख करोड़ रियायती ऋण प्रोत्साहन	<ul style="list-style-type: none"> ● 1.35 लाख करोड़ की क्रेडिट सीमा के साथ 1.5 करोड़ से अधिक केसीसी जारी किए गए
	पीएम स्वनिधि योजना शहरी पथ विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए	<ul style="list-style-type: none"> ● 30.11.2021 तक 30.2 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को ब 3,054 करोड़ का ऋण
	स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)	<ul style="list-style-type: none"> ● संपार्श्विक मुक्त ऋण सीमा ₹ 10 लाख से बढ़ाकर ₹ 20 लाख 63 लाख महिला एसएचजी, जिन्होंने 6.85 करोड़ परिवारों का समर्थन किया।
	दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करके गरीबी कम करने के लिए	<ul style="list-style-type: none"> ● 2020-21: एसएचजी को वितरित किए गए ₹ 84,143 करोड़ के ऋण। ● 2021-22 (सितंबर 2021 तक): 21.6 लाख एसएचजी ऋण ब 43093 करोड़ से जुड़े।
	एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआई के लिए ₹ 30,000 करोड़ की विशेष चलनिधि योजना	<ul style="list-style-type: none"> ● 30.09.2020 तक, 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जिसमें ₹ 11,120 करोड़ - ₹ 7,227 करोड़ संवितरित शामिल थे। योजना बंद कर दी गई है।
कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ₹ 1.1 लाख करोड़ की ऋण गारंटी योजना - स्वास्थ्य अवसंरचना, पर्यटन, आदि।	<ul style="list-style-type: none"> ● 30.06.2021 को कैबिनेट की मंजूरी ● 31.03.2022 तक या ₹ 50,000 करोड़ स्वीकृत होने तक, जो भी पहले हो, लागू है 	

स्रोत: विभिन्न पीआईबी विज्ञप्ति, संसदीय प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक

मौद्रिक और वित्तीय सहायता

1.24 महामारी के प्रकोप के चलते मौद्रिक नीति को आर्थिक वृद्धि को समर्थन प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, वहीं अतिरिक्त नकदी के मध्यम अवधि के विस्थापन से बचने के लिए सावधानीपूर्वक नियंत्रित भी किया गया था। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने फरवरी से मई 2020 के दौरान नीति रेपो दर में 115

आधार अंकों (बीपीएस) की कटौती की, पिछले बारह महीनों में 135 बीपीएस की कमी के ऊपर। तब से, एमपीसी ने नीति रेपो दर पर यथास्थिति बनाए रखी है और इसे 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है। सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर भी 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है और इसलिए रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत है। आरबीआई ने अपने नवीनतम एमपीसी बयान में आगे भी इस उदार रुख को जारी रखने का फैसला किया है, जब तक कि टिकाऊ आधार पर विकास को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक हो। केंद्र और राज्य सरकारों को कम दरों पर वित्तपोषित करने के लिए एवं प्रणाली में पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करने के लिए कई अतिरिक्त कदम उठाए गए।

1.25 सुरक्षा-जाल का एक महत्वपूर्ण पहलू सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकारी गारंटियों का उपयोग था (तालिका 5 देखें)। दिवाला कार्यवाही पर स्थगन के साथ, सरकार एक भुगतान गतिरोध से बचने में सक्षम थी जो कि चूक का एक जलप्रपात हो सकता था। जहां जरूरत थी वहां अधिकांश समर्थन 2021-22 में बढ़ा दिया गया था, लेकिन आरबीआई और सरकार ने कुछ नकदी समर्थन को रोल-ऑफ और दिवाला प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है क्योंकि अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। ऐसा करना महत्वपूर्ण है क्योंकि अतिरिक्त नकदी और एक रुकी हुई दिवाला प्रक्रिया लंबी अवधि के जोखिम लाती है। इस पर अध्याय 4 में विस्तार से चर्चा की गई है।

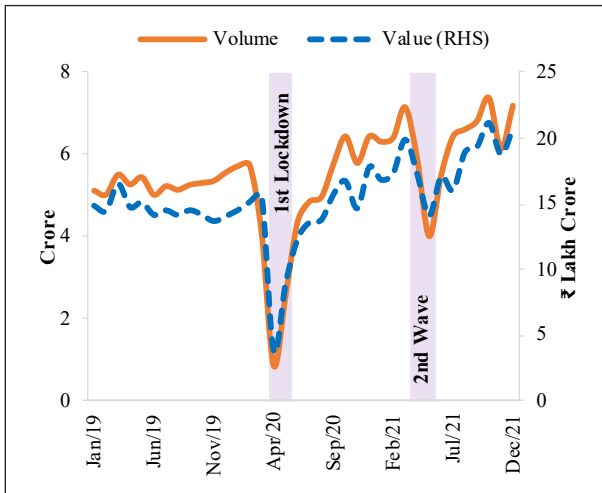
उच्च आवृत्ति संकेतक

1.26 जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पिछले दो वर्षों में, सरकार ने सार्वजनिक और निजी दोनों स्रोतों से उद्योग, सेवाओं, वैश्विक प्रवृत्तियों, वृहद्-आर्थिक-स्थिरता संकेतकों और कई अन्य गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अस्सी एचएफआई की एक श्रृंखला का लाभ उठाया है ताकि रीयल टाइम आधार पर अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित स्थिति का आकलन किया जा सके। इनमें गतिशीलता आंकड़े, बिजली उत्पादन, अनुसूचित घरेलू उड़ानें, वित्तीय लेनदेन की मात्रा/मूल्य, पूंजीगत प्रवाह आदि शामिल हैं। इसमें ग्रामीण रोजगार की स्थिति, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के संदर्भ में, मनरेगा के तहत मांगे गए रोजगार को भी शामिल किया गया है। इन संकेतकों को वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक रिपोर्ट में नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है और इस अध्याय के अंत में एक पूरी सूची अनुबंध में दी गई है।

1.27 भले ही, एचएफआई का रीयल-टाइम और लगातार होने का फायदा है, उन्हें सावधानी से उपयोग करने की आवश्यकता है। प्रत्येक संकेतक, सर्वोत्तम रूप से, विकास का आंशिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसके अलावा, शोर-से-संकेत अनुपात राष्ट्रीय खातों और अन्य धीमी गति से चलने वाले आंकड़ों की तुलना में अधिक हो सकता है। बहरहाल, तेजी से विकसित हो रही स्थिति में, नीति-निर्माता उपयोगी संकेत प्राप्त कर सकते हैं जो तेजी से प्रतिक्रिया और बेहतर लक्ष्यीकरण की अनुमति देते हैं। इस प्रकार, अर्थव्यवस्था में प्रवृत्तियों का आकलन करने के लिए एचएफआई का उपयोग करना उतनी ही कला है जितना कि विज्ञान। निम्नलिखित चित्र इस्तेमाल किए जा रहे एचएफआई का एक अनुमान प्रदान करते हैं (चित्र 25)। प्रासंगिक अध्यायों में विशिष्ट व्याख्याओं और नीति प्रतिक्रिया पर चर्चा की गई है।

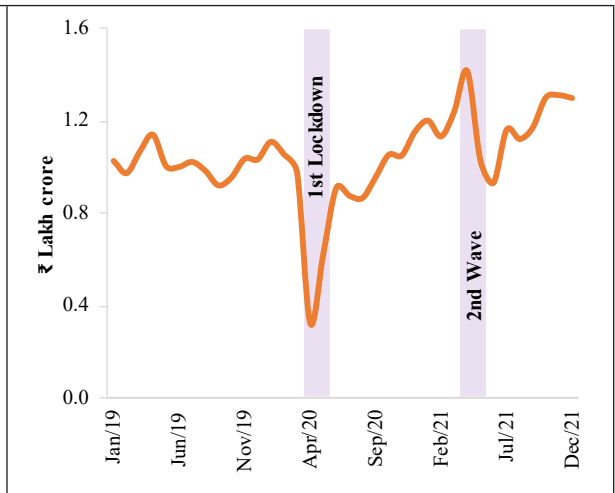
चित्र 25: उच्च आवृत्ति संकेतकों का प्रदर्शन

क. ई-वे बिल जनरेशन



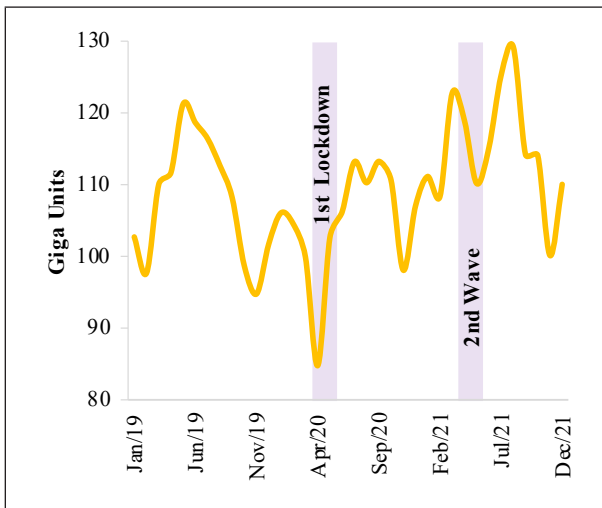
स्रोत: जीएसटीएन

ख. जीएसटी संग्रह



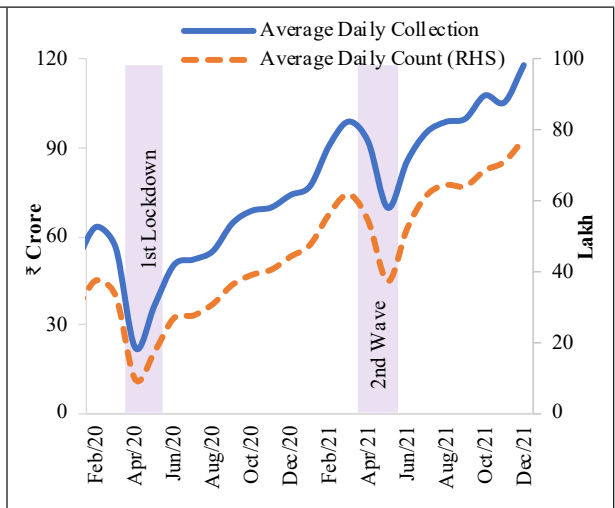
स्रोत: वित्त मंत्रालय

ग. बिजली की खपत

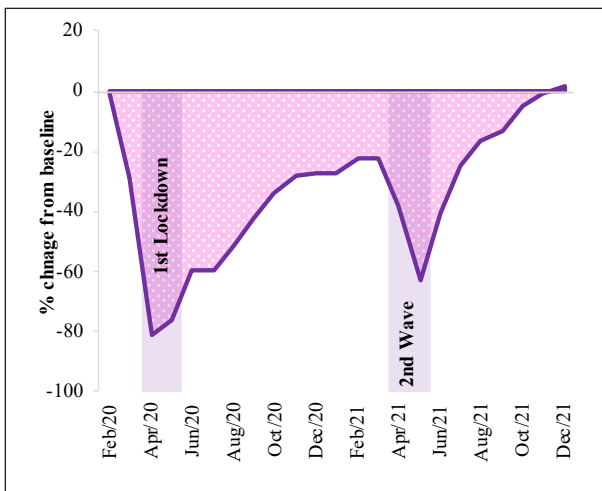


स्रोत: पीओएसओसीओ

घ. ईटीसी टोल संग्रह और गणना

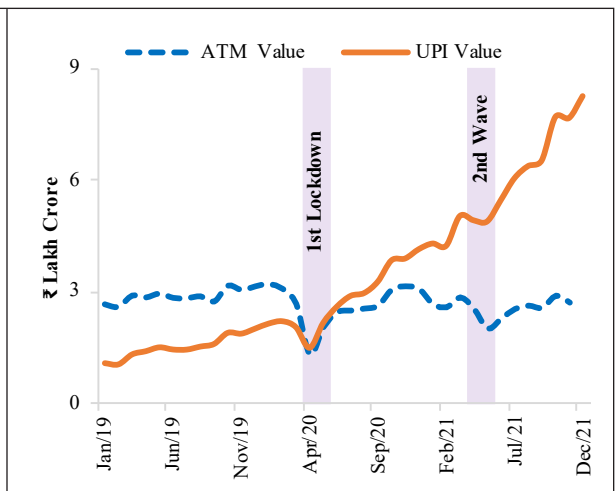


ङ. खुदरा गतिशीलता



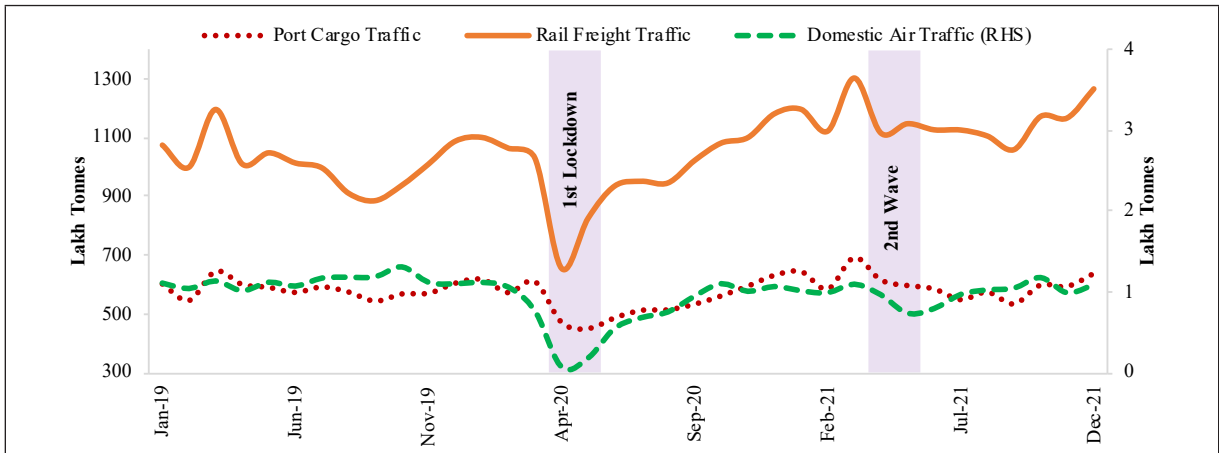
स्रोत: गूगल मोबिलिटी

च. यूपीआई और एटीएम लेनदेन



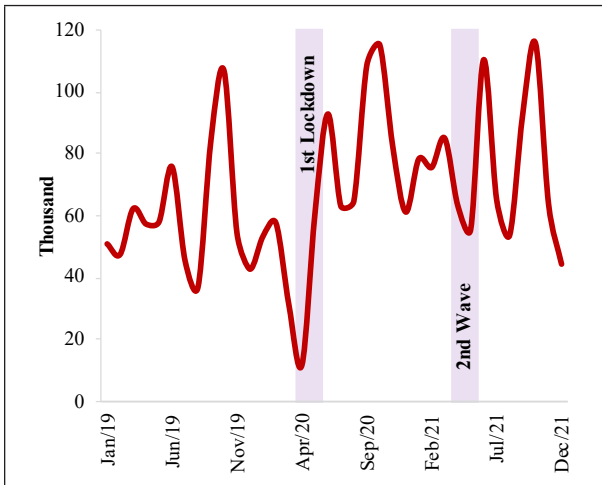
स्रोत: आईएचएस मार्किट

छ. माल और कार्गो यातायात



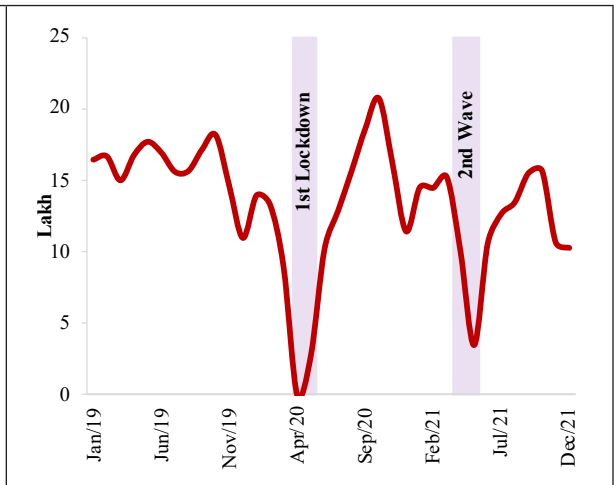
स्रोत: आईपीए, एएआई, रेल मंत्रालय

ज. घरेलू ट्रैक्टर बिक्री



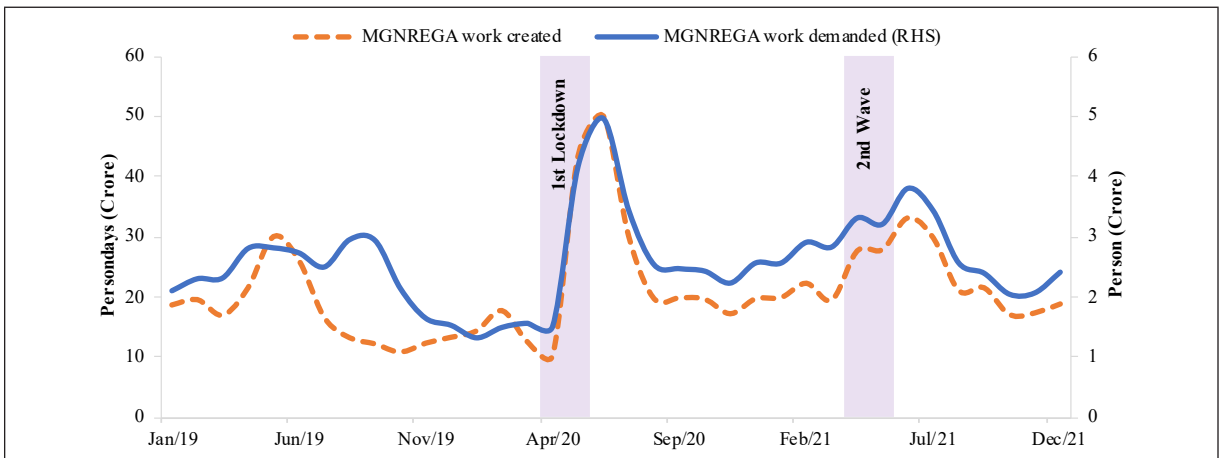
स्रोत: टीएमए

झ. दो और तीन वाहनों की बिक्री



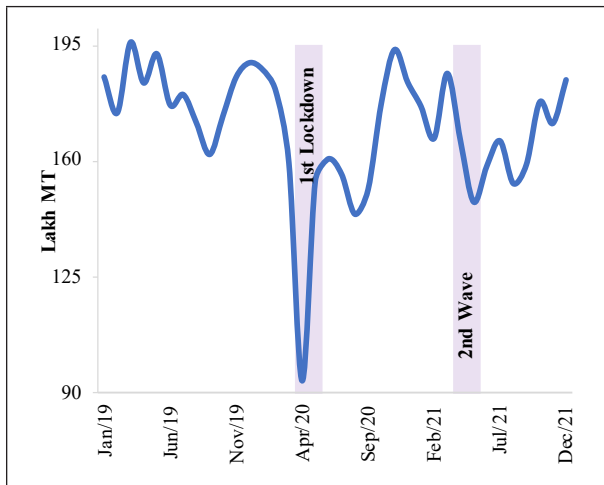
स्रोत: सियाम

ञ. मनरेगा का काम सृजित और मांगा



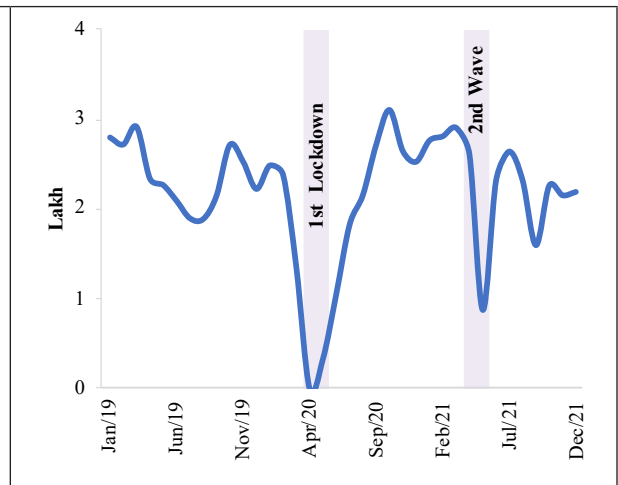
स्रोत: नरेगा सॉफ्ट

ट. ईंधन की खपत



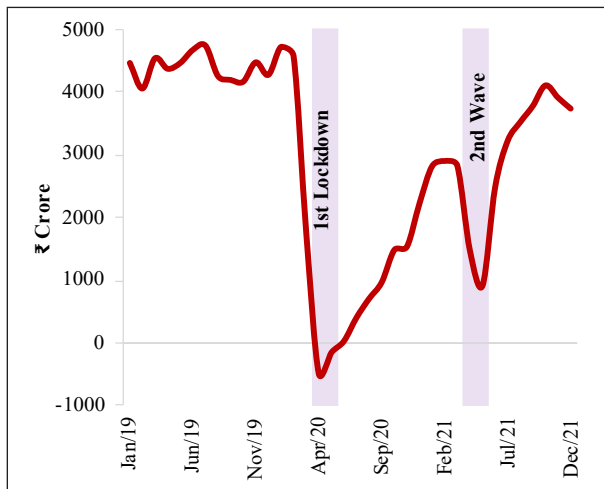
स्रोत: एनपीसीआई

ठ. यात्री वाहन बिक्री



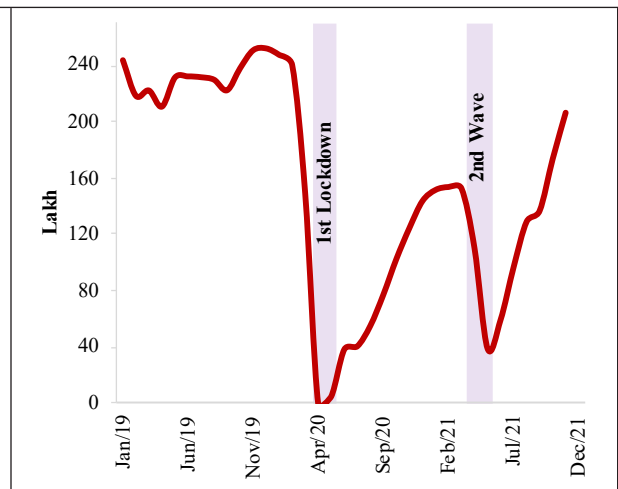
स्रोत: आरबीआई

ड. रेलवे यात्री आय

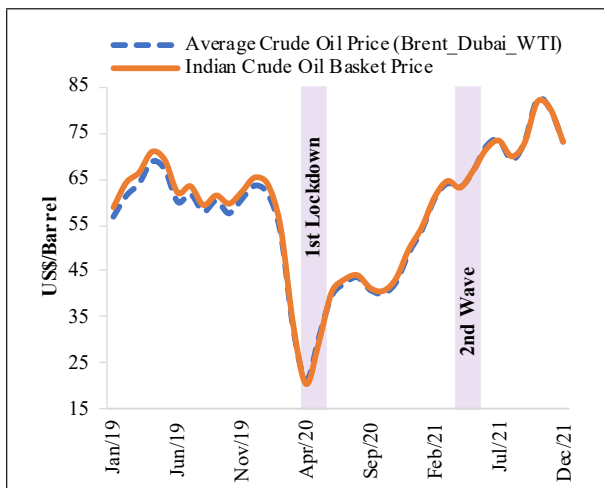


स्रोत: रेल मंत्रालय, एएआई

ढ. हवाई यात्री यातायात

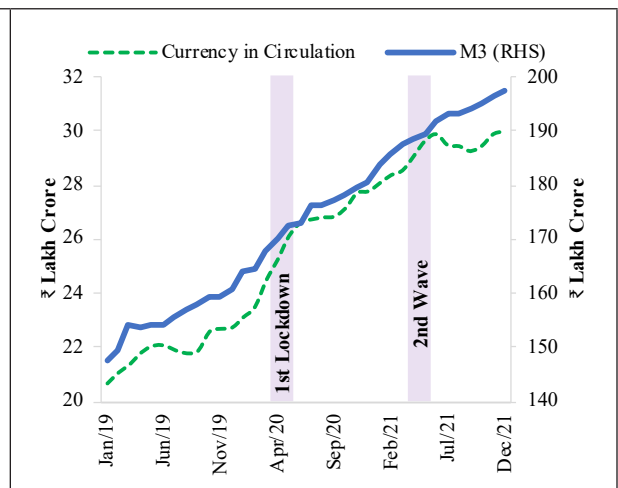


ण. कच्चे तेल की कीमत



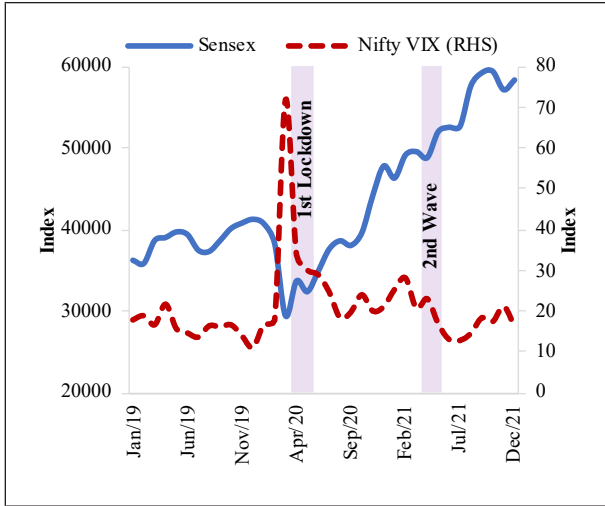
स्रोत: पीपीएसी

त. संचलन और मुद्रा आपूर्ति में मुद्रा



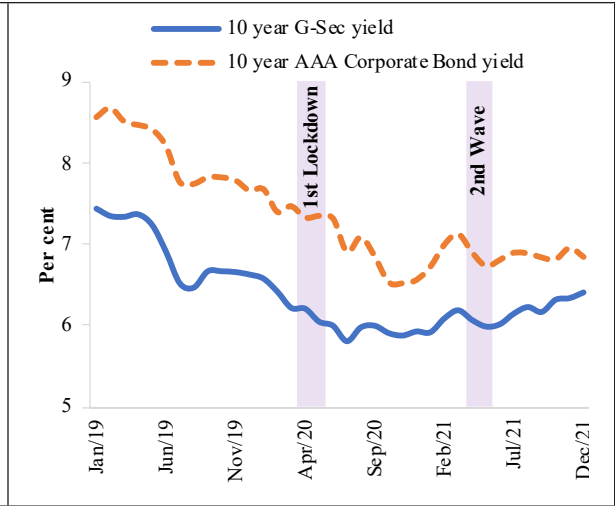
स्रोत: आरबीआई

थ. इक्विटी बाजार



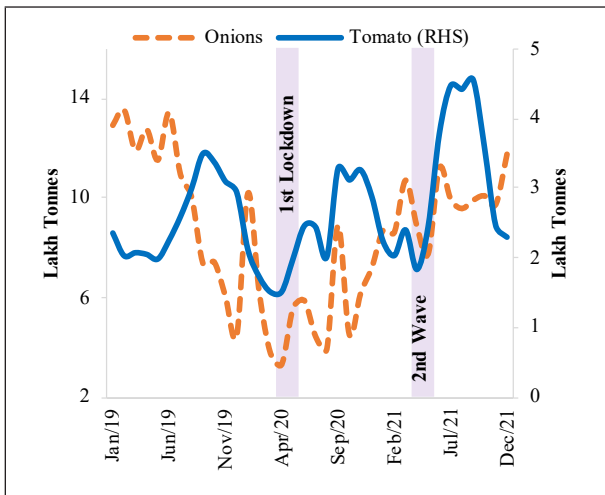
स्रोत: एनएसई, बीएसई

द. बांड आय



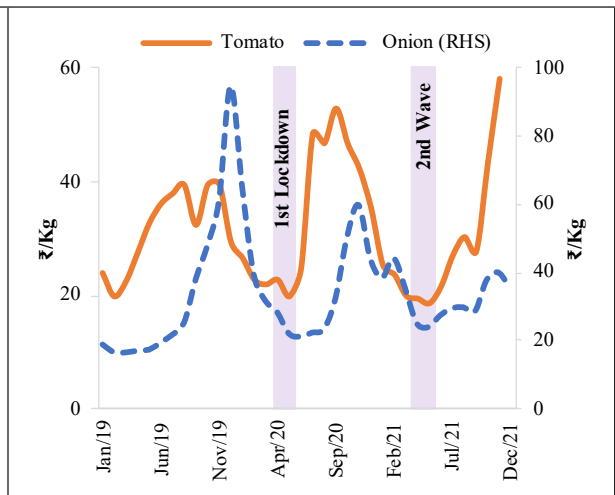
स्रोत: सीसीआईएल

ध. मंडी आमद



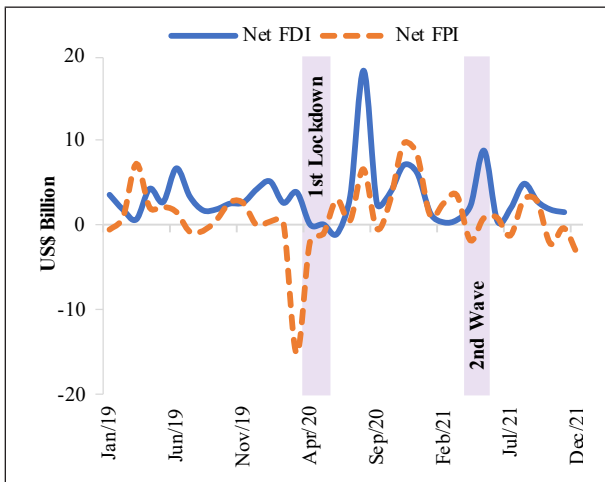
स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग, सीएमआईई

न. खुदरा मूल्य



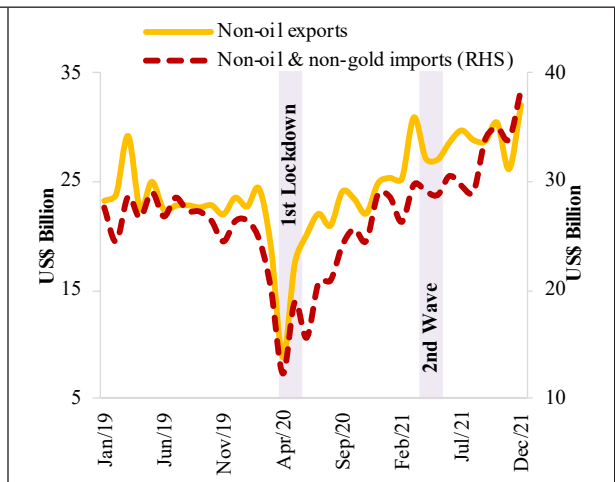
स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग, सीएमआईई

प. एफडीआई और एफपीआई



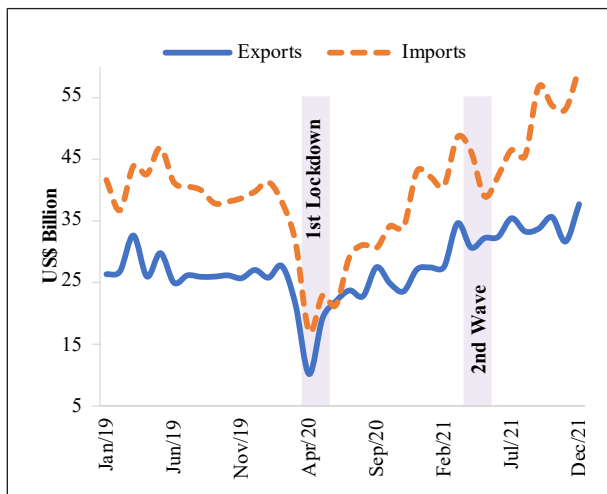
स्रोत: सीडीएसएल

फ. गैर-तेल आयात और निर्यात



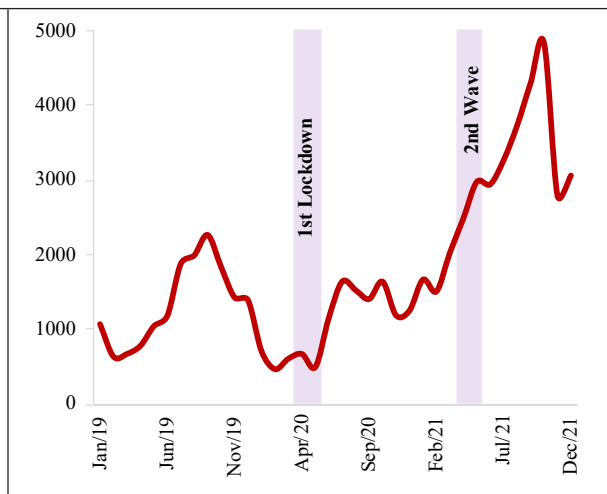
स्रोत: आरबीआई, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

ब. विदेशी व्यापार



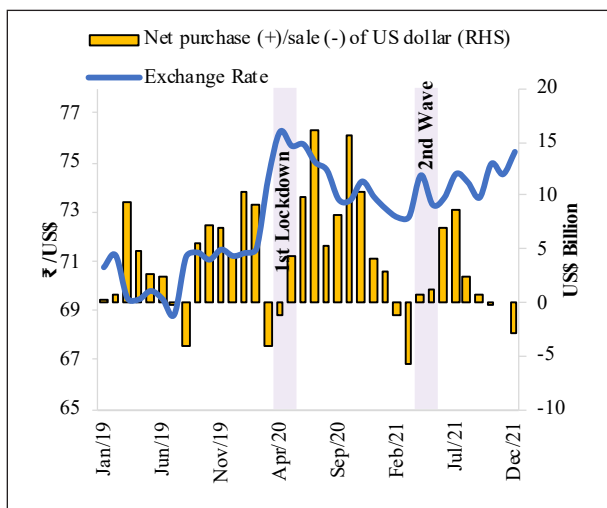
स्रोत: वाणिज्य मंत्रालय

भ. बाल्टिक ड्राई इंडेक्स



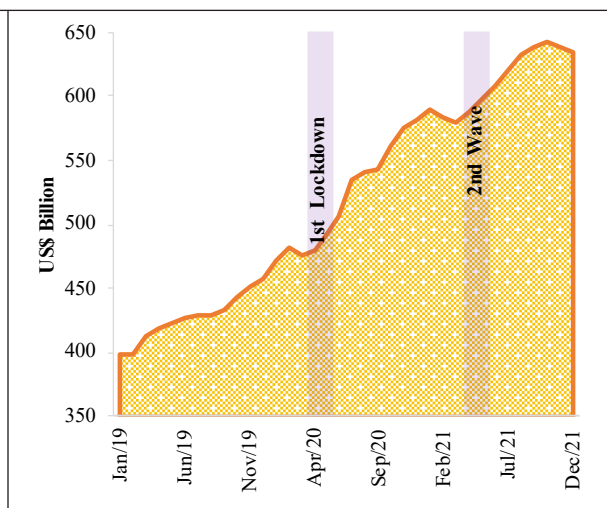
स्रोत: द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड

म. डॉलर की निवल बिक्री/खरीद और विनिमय दर



स्रोत: आरबीआई

य. विदेशी मुद्रा भंडार

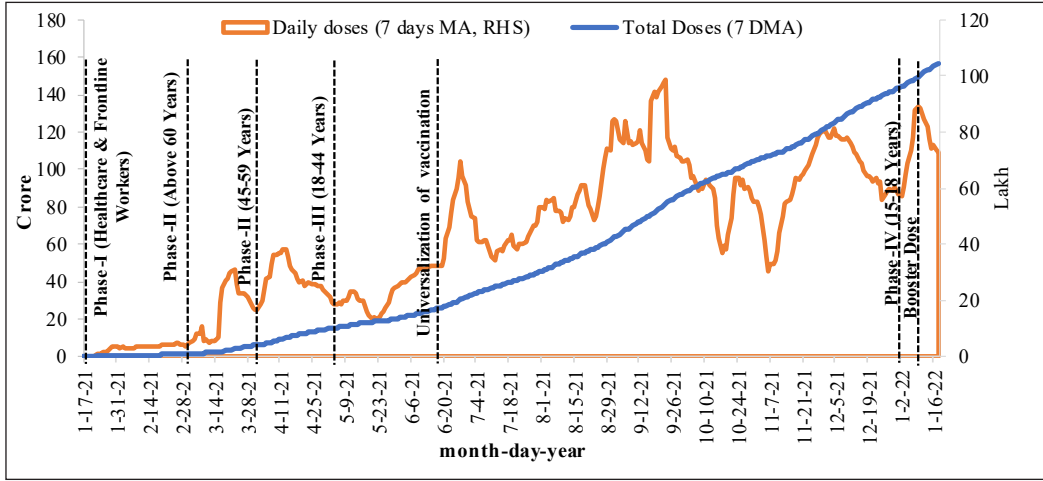


स्रोत: आरबीआई

टीकाकरण

1.28 टीकाकरण ने जीवन के नुकसान को कम करने, कार्यकलापों को फिर से शुरू करने हेतु अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ाने और दूसरी लहर के कारण उत्पादन में क्रमिक गिरावट को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है (बॉक्स 1)। जब भारत ने 16 जनवरी, 2022 को अपने कोविड-19 टीकाकरण अभियान का एक वर्ष पूरा किया, वैक्सीन की 156 करोड़ से अधिक खुराक (चित्र 26) के व्यवस्था के ऐतिहासिक उपलब्धि को पार कर लिया गया था। 88 करोड़ से अधिक लोगों (वयस्क आबादी का 93 प्रतिशत) को कम से कम एक खुराक मिली है, जिसमें से लगभग 66 करोड़ लोगों (वयस्क आबादी का 70 प्रतिशत) का पूरी तरह से टीकाकरण किया गया है। 3 जनवरी, 2022 से शुरू होने वाले 15-18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाने सहित इस आयु वर्ग में भारत की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी को 19 जनवरी तक टीके की पहली खुराक मिल गई है। इन उपायों पर अध्याय 10 में विस्तार से चर्चा की गई है।

चित्र 26: टीकाकरण की विस्तृत सूचना



स्रोत: एमओएचएफडब्ल्यू से डेटा का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण गणना

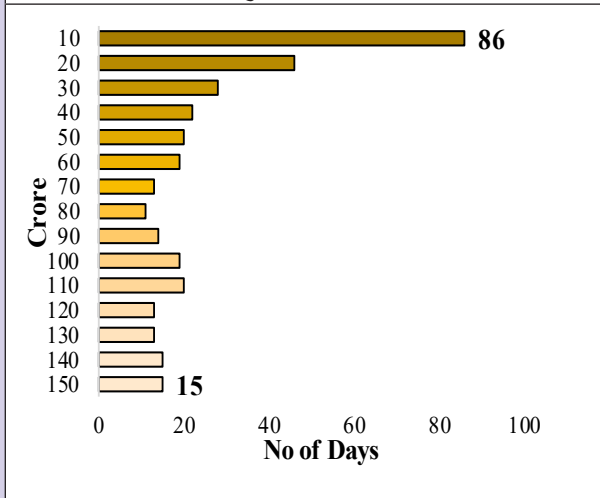
1.29 दिसंबर 2021 के अंत से भारत में दैनिक नए मामलों में पुनरुत्थान सहित ओमीक्रोन संस्करण की तीसरी लहर की शुरुआत को चिह्नित करते हुए, टीकाकरण में तेजी से प्रगति और परीक्षण और स्वास्थ्य अवसंरचना को और सुदृढ़ करना जीवन की रक्षा और संक्रमण के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण महत्व रखता है।

बॉक्स 1: भारत का टीकाकरण अभियान

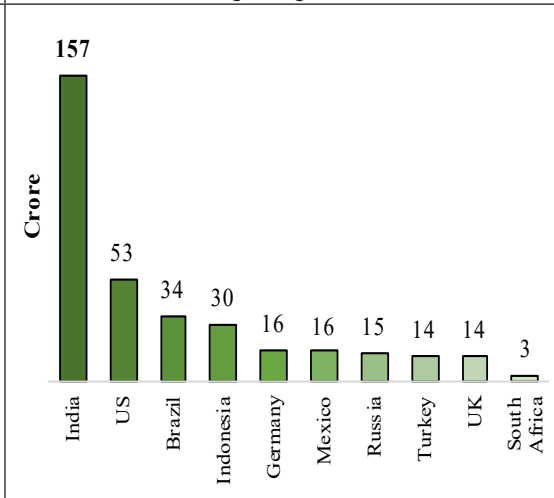
महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए टीकाकरण भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अभिन्न स्तंभ रहा है। 16 जनवरी 2021 को, भारत ने 31 दिसंबर 2021 तक अपनी पूरी आबादी को कम से कम पहली खुराक के साथ टीका लगाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया था। पहले चरण में, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता और फ्रंट लाइन कर्मचारियों को शामिल करने के लिए टीकाकरण अभियान का क्रमिक रूप से विस्तार किया गया था। दूसरा चरण 1 मार्च (60 वर्ष से अधिक के लिए) और 1 अप्रैल 2021 (45-59 वर्ष से) को शुरू हुआ था, जिससे 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति टीकाकरण के लिए पात्र हो गए थे। गौरतलब है कि देश में कोविड-19 के कारण हुई मौतों में से 80 प्रतिशत मौतें इसी आयु वर्ग में रहीं थीं। तीसरा चरण 1 मई 2021 को 18-45 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण करने के लिए शुरू किया गया था। दिनांक 3 जनवरी 2022 से, टीकाकरण अभियान को 15-18 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को शामिल करने के लिए आगे बढ़ाया गया है। सरकार द्वारा ओमिक्रोन वेरिएंट के हालिया वैश्विक संक्रमण का संज्ञान लेते हुए, 26 नवंबर 2021 को डब्ल्यूएचओ द्वारा घोषित मुद्दा का संस्करण, स्वास्थ्य देखभाल और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के साथ-साथ 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सह-रुग्णता सहित बूस्टर खुराक की अनुमति दी गई है। 10 जनवरी 2022 से। राज्यों और सभी आयु समूहों में टीकाकरण की गति को तेज करने के लिए टीकाकरण पहुंच और मूल्य निर्धारण को नियंत्रित कर दिया गया है।

लेखन के समय उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि 99 प्रतिशत पंजीकृत स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता और 100 प्रतिशत फ्रंट-लाइन कार्यकर्ता, 18-44 वर्ष की आयु के बीच 87 प्रतिशत जनसंख्या, 45-60 वर्ष की आयु के बीच 95 प्रतिशत जनसंख्या और 60 वर्ष से ऊपर की 89 प्रतिशत जनसंख्या को पहली खुराक के तहत टीकाकरण किया गया है। टीकाकरण अभियान की गति और चाल बढ़ती जा रही है और अतिरिक्त 10 करोड़ खुराक प्राप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या प्रारंभिक चरण के दौरान 86 दिनों से घटकर अब 15 दिन हो गई है (चित्र 1क)। औसत दैनिक टीकाकरण दर मई 2021 में 19.3 लाख से बढ़कर 16 जनवरी 2021 तक 75.4 लाख हो गई है। 16 जनवरी 2022 तक, भारत में पहली खुराक लेने वाले पात्र आबादी (18 वर्ष और अधिक) का टीकाकरण 93 प्रतिशत था। दूसरी खुराक लेने वाले पात्र आबादी 69.8 प्रतिशत (चित्र 1सी) था।

चित्र 1क: भारत में अगले 10 करोड़ खुराक तक पहुंचने के लिए दिन

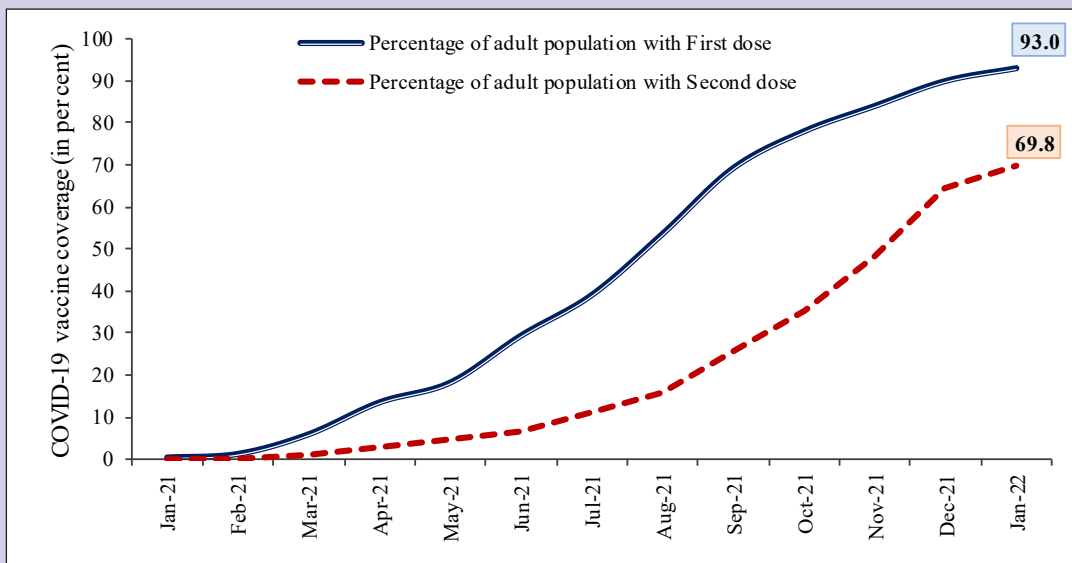


चित्र 1ख: देशों में व्यवस्थित कुल खुराक



स्रोत: एमओएचएफडब्ल्यू और डब्ल्यूएचओ के डेटा का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण गणना
टिप्पणी: 16 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार चित्र 1ख आंकड़े।

चित्र 1ग: कोविड-19 वैक्सीन सहित वयस्क जनसंख्या का संचयी प्रतिशत (प्रतिशत में)



स्रोत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के डेटा के उपयोग द्वारा सर्वेक्षण गणना
नोट: 16 जनवरी 2022 तक के आंकड़े

वृहद्-आर्थिक स्थिरता

1.30 लेखन के समय, ओमिक्रोन संस्करण के रूप में एक नई लहर दुनिया भर में फैल रही थी, अधिकांश देशों में मुद्रास्फीति बढ़ गई थी, और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा नकदी की निकासी का चक्र शुरू किया जा रहा था। यही कारण है कि भारत के वृहद्-आर्थिक स्थिरता संकेतकों और उपरोक्त तनावों के खिलाफ एक बफर प्रदान करने की उनकी क्षमता को देखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सारणी-6 में 2008-09 (वैश्विक वित्तीय संकट), 2012-13 (टेपर टैट्रम) और 2021-22 (कोविड -19 महामारी का दूसरा वर्ष) में विभिन्न वृहत् आर्थिक स्थिरता संकेतकों की त्वरित तुलना की गई है। यह खंड सभी अग्रणी- विदेशी क्षेत्र, राजकोषीय संकेतक, वित्तीय क्षेत्र और मुद्रास्फीति पर वृहत् आर्थिक स्थिरता संकेतकों का विश्लेषण करता है-

सारणी 6: वैश्विक वित्तीय संकट, टेंपर टैंट्रम और कोविड-19 के दौरान वृहत आर्थिक संकेतकों की तुलना

	वैश्विक वित्तीय संकट	टेंपर टैंट्रम	कोविड-19 वैश्विक महामारी	
वृहत आर्थिक संकेतक	2008-09	2012-13	2021-22	
सीपीआई मुद्रास्फीति	9.1	9.4	5.2	अप्रैल-दिसंबर 2021
सकल घरेलू उत्पाद के% के रूप में भारत का सकल राजकोषीय घाटा	8.3	6.9	10.2	2021-22 (ब.अ)
जीडीपी के% के रूप में ईएमडीई (एशिया) का राजकोषीय घाटा	1.6	1.7	7.8	2021
सकल घरेलू उत्पाद के% के रूप में चालू खाता शेष	-2.3	-4.8	-0.2	अप्रैल-सितंबर 2021
सकल घरेलू उत्पाद के% के रूप में विदेशी ऋण	20.7	22.4	20.2	जून 2021
विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	252	292	634	31 दिसंबर 2021
सरकारी बॉन्ड यील्ड 10-वर्ष	7.3	8.0	6.4	11 जनवरी 2022
कुल एफडीआई अंतर्वाह (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	8.3	34.0	48.4	अप्रैल-अक्टूबर 2021
जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) के लिए एससीबी की पूंजी	13.2	13.9	16.5	सितंबर 2021
एससीबी प्रावधान कवरेज अनुपात	-	47.6	68.1	सितंबर 2021

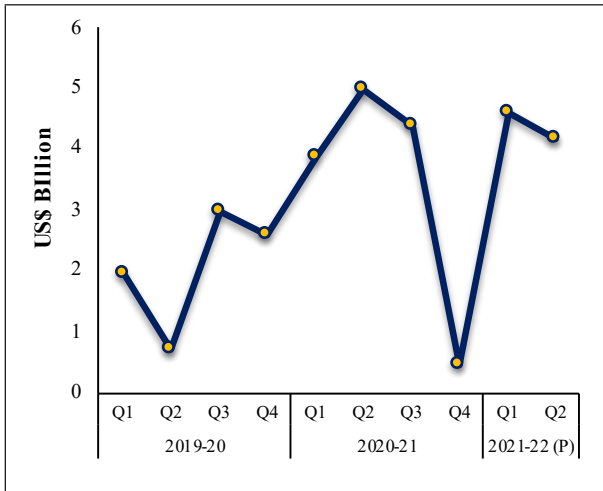
स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई, आरबीआई, सीजीए, सीडीएसएल, वित्त मंत्रालय, आईएमएफ

नोट: टेंपर टैंट्रम स्थिति 2013 में उत्पन्न हुई थी। उपरोक्त तालिका में, 2012-13 का उपयोग टेंपर टैंट्रम से ठीक पहले की स्थिति को दिखाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह वित्तीय बाजारों में तरलता की वापसी से पहले की वर्तमान स्थिति के अनुरूप है।

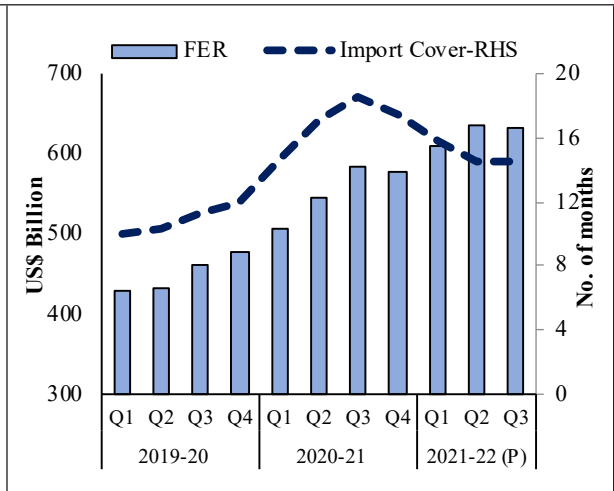
विदेशी क्षेत्र

1.31 वैश्विक महामारी के कारण हुए सभी व्यवधानों के बावजूद, पिछले दो वर्षों में भारत का भुगतान संतुलन अधिशेष में रहा (चित्र 27)। इसने भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा भंडार जमा करने का अवसर दिया, जो 31 दिसंबर 2021 को 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह 13.2 महीने के व्यापारिक आयात (चित्र 28) के बराबर है और देश के विदेशी ऋण से अधिक है। नवंबर 2021 के अंत तक, भारत चीन, जापान और स्विटजरलैंड के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था। भंडार में बड़ी वृद्धि के कारण विदेशी मुद्रा भंडार और कुल विदेशी ऋण के अनुपात, अल्पकालिक ऋण और विदेशी मुद्रा भंडार के अनुपात आदि जैसी विदेशी भेद्यता संकेतकों में सुधार हुआ।

चित्र 27: बीओपी संतुलन में अधिशेष



चित्र 28: विदेशी मुद्रा भंडार और शामिल किए गए आयात



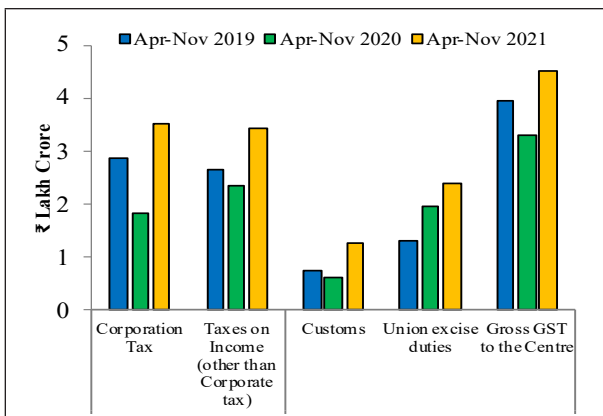
स्रोत: आरबीआई

1.32 इस समय, भारत के मुख्य विदेशी क्षेत्र स्थिरता संकेतक वैश्विक वित्तीय संकट या 2013 के टेपर ट्रैट्रम (मुद्रिक तरलता की निकासी की घटना) की तुलना में मजबूत और बेहतर हैं। उदाहरण के लिए, शामिल किए गए आयात और विदेशी मुद्रा भंडार अब दोगुने से अधिक हैं। उच्च विदेशी मुद्रा भंडार, निरंतर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और बढ़ती निर्यात आय का संयोजन 2022-23 में किसी भी नकदी की कमी/मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के स्थान पर अच्छा बफर प्रदान करेगा (विवरण अध्याय 3 में)।

राजकोषीय शेष

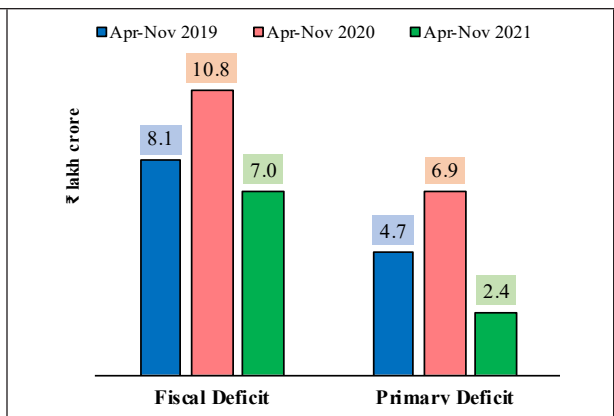
1.33 अर्थव्यवस्था को दिए गए वित्तीय समर्थन के साथ-साथ स्वास्थ्य प्रतिक्रिया के कारण 2020-21 में राजकोषीय घाटा और सरकारी ऋण में वृद्धि हुई है। तथापि, 2021-22 में अब तक सरकारी राजस्व में जोरदार उछाल देखने को मिला है। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में 67.2 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई है, जबकि 2021-22 के बजट अनुमानों में 9.6 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि हुई है। कर संग्रह प्रत्यक्ष करें और अप्रत्यक्ष करें दोनों के लिए उत्साहित रहा है (चित्र 29)। सकल मासिक जीएसटी संग्रह जुलाई 2021 से लगातार ₹ 1 लाख करोड़ को पार कर गया है (अध्याय 2 में विवरण)।

चित्र 29: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर राजस्व



स्रोत: सीजीए का कार्यालय

चित्र 30: राजकोषीय और प्राथमिक घाटा



स्रोत: सीजीए का कार्यालय

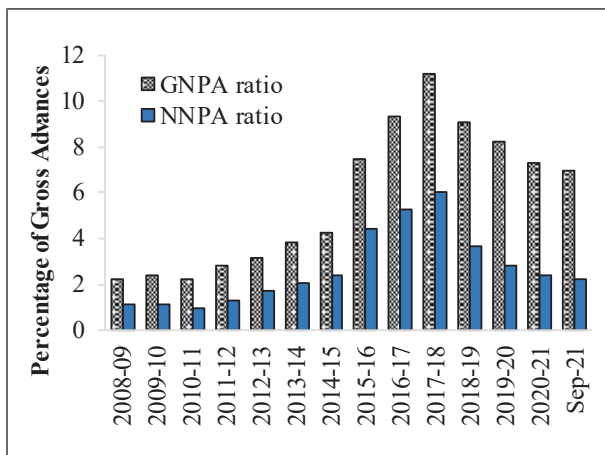
1.34 भारत सरकार द्वारा निरंतर राजस्व संग्रह और लक्षित व्यय नीति के कारण, अप्रैल-नवंबर 2021 के लिए राजकोषीय घाटा ब.अ. के 46.2 प्रतिशत पर समाहित किया गया है जो कि पिछले दो वर्षों (अप्रैल-नवंबर 2020 में ब.अ. का 135.1% और अप्रैल-नवंबर 2019 में ब.अ. का 114.8%) में इसी अवधि के दौरान प्राप्त अनुपात का लगभग एक तिहाई है। अप्रैल से नवंबर 2021 की अवधि के दौरान प्राथमिक घाटा अप्रैल से नवंबर 2019 के दौरान उस स्तर के लगभग आधे पर पहुंच गया, जो अप्रैल से नवंबर 2019 के दौरान पहुंच गया था। (चित्र 30) इससे संकेत मिलता है कि सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए और पूंजीगत व्यय बढ़ाते हुए इस वर्ष के अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगी। राजस्व में मजबूत पुनरुद्धार, यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए सरकार को वित्तीय स्थान भी प्रदान करता है।

वित्तीय क्षेत्र

1.35 वित्तीय प्रणाली हमेशा अशांत समय के दौरान तनाव का एक संभावित क्षेत्र होता है। हालांकि, भारत के पूंजी बाजारों ने, कई वैश्विक बाजारों की तरह, असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है और भारतीय कंपनियों के लिए जोखिम पूंजी के रिकॉर्ड जुटाने की अनुमति दी है। सेंसेक्स और निफ्टी 18 अक्टूबर, 2021 को 61,766 और 18,477 पर अपने चरम को छूने के लिए बढ़े। प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, भारतीय बाजारों ने अप्रैल-दिसंबर 2021 में अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन किया। कई नए युग की कंपनियों/तकनीकी स्टार्ट-अप्स/यूनिकॉर्न्स द्वारा आईपीओ के माध्यम से धन उगाहने में तेजी के साथ प्राथमिक बाजार के लिए वर्ष 2021-22 अब तक के लिए एक असाधारण वर्ष रहा है। अप्रैल-नवंबर 2021 में जारी किये गये 75 आईपीओ के माध्यम से ₹ 89,066 करोड़ जुटाए गए, जो पिछले दशक में किसी भी वर्ष की तुलना में बहुत अधिक है (विवरण अध्याय 4 में)।

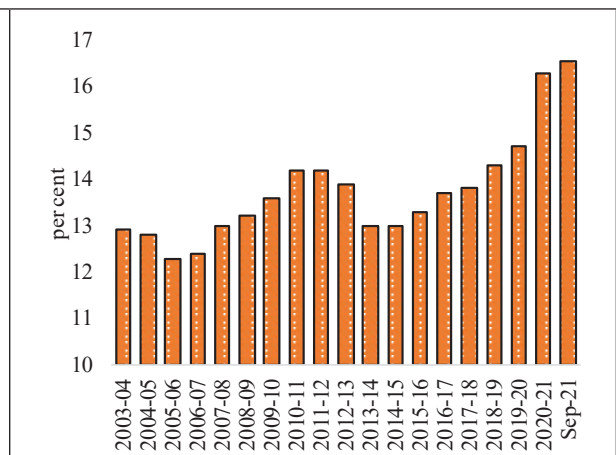
1.36 अधिक महत्वपूर्ण रूप से, बैंकिंग प्रणाली अच्छी तरह से पूंजीकृत है और गैर-निष्पादित आस्तियों में, महामारी के विलम्बित प्रभाव को मिलाकर भी, संरचनात्मक रूप से गिरावट आई है, यहां तक कि महामारी के कुछ कम प्रभाव से अनुमति भी दी गई है। 2018-19 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के सकल गैर-निष्पादित अग्रिम (जीएनपीए) अनुपात (अर्थात सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में जीएनपीए) और शुद्ध गैर-निष्पादित (एनएनपीए) अनुपात में गिरावट जारी है। एससीबी का जीएनपीए अनुपात सितंबर 2020 के अंत में 7.5 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2021 के अंत में 6.9 प्रतिशत हो गया। एससीबी का एनएनपीए अनुपात भी 2017-18 के अंत में 6 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2021 के अंत में 2.2 प्रतिशत हो गया। चित्र 31)। साथ ही, 2015-16 से पूंजी पर्याप्तता अनुपात में सुधार जारी है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंकों (चित्र 32) में सुधार के कारण एससीबी का पूंजीगत जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) सितंबर 2020 के अंत में 15.84 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2021 के अंत में 16.54 प्रतिशत हो गया। (चित्र 32)

चित्र 31: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जीएनपीए और एनएनपीए अनुपात



स्रोत: आरबीआई

चित्र 32: पूंजी पर्याप्तता अनुपात (प्रतिशत)

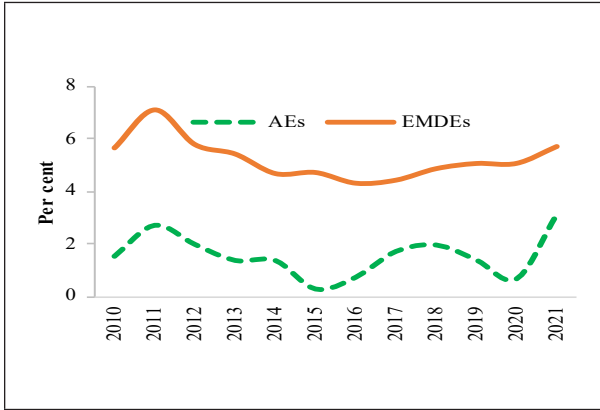


स्रोत: आरबीआई

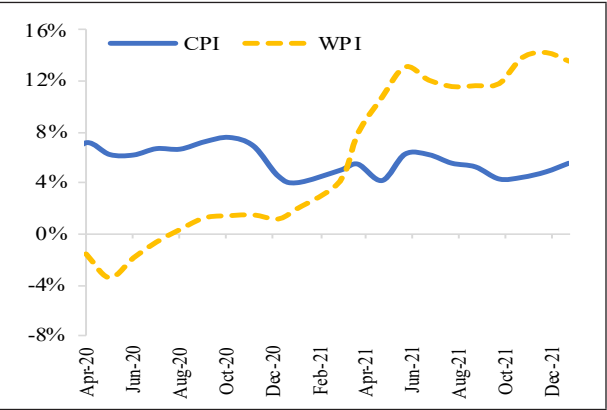
मुद्रास्फीति

1.37 उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति एक वैश्विक मुद्दे के रूप में फिर से प्रकट हुई है (चित्र 33)। ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि, गैर-खाद्य वस्तुओं, इनपुट कीमतों, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, और बढ़ती माल ढुलाई लागत ने वर्ष के दौरान वैश्विक मुद्रास्फीति को रोक दिया। भारत में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में घटकर 5.2 प्रतिशत हो गई, जो 2020-21 की इसी अवधि में 6.6 प्रतिशत थी। दिसंबर 2021 में यह 5.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) था, जो लक्षित सीमा के भीतर है (चित्र 34)। 2021-22 में खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में कमी हुई है। (अध्याय 5 में विवरण)। हालांकि थोक मूल्य मुद्रास्फीति, दो अंकों में चल रही है। थोक मूल्य सूचकांक के 'ईंधन और बिजली' समूह में मुद्रास्फीति 20 प्रतिशत से ऊपर थी जो उच्च अंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम कीमतों को दर्शाती है। हालांकि उच्च डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति आंशिक रूप से आधार प्रभावों के कारण है जो कि बाहर भी होंगे, भारत को आयातित मुद्रास्फीति, विशेषतः उच्च वैश्विक ऊर्जा कीमतों से सावधान रहने की आवश्यकता है।

चित्र 33: उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति दरें



चित्र 34: सीपीआई और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति



स्रोत: विश्व आर्थिक आउटलुक, जनवरी 2022 अपडेट, आईएमएफ टिप्पणी: वार्षिक औसत के आंकड़े; 2021 के अनुमानित आंकड़े

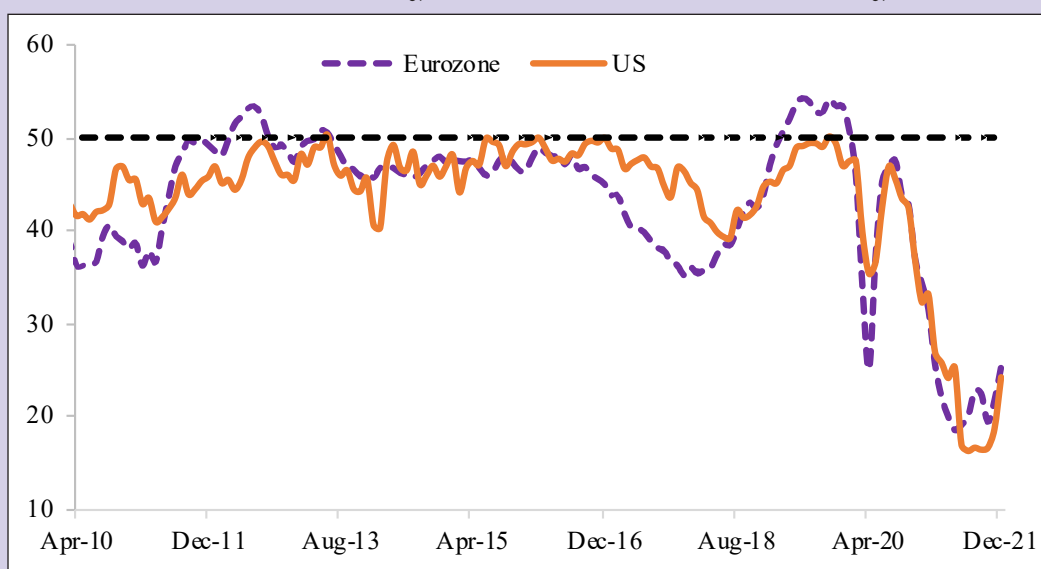
स्रोत: एमओएसपीआई, डीपीआईआईटी

1.38 कुल मिलाकर, वृहद-आर्थिक स्थिरता संकेतक बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 की चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है।

बॉक्स 2: वैश्विक आपूर्ति-पक्ष व्यवधान

जैसा कि 2021 में विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, इसे वितरण में देरी, कंटेनर की कमी और सेमीकंडक्टर चिप की कमी से लेकर गंभीर आपूर्ति-पक्ष बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार, “... कोविड-19 महामारी के कारण अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में अचानक गिरावट आई। लेकिन 2020 के अंत तक मुख्य रूप से एक कंटेनर और ड्राई बल्क शिपिंग में तेजी से बदलाव हुआ था। कंटेनर व्यापार प्रवाह में सुधार, जो मुख्य रूप से पूर्व-पश्चिम कंटेनरीकृत व्यापार लेन पर था, ने लॉजिस्टिक चुनौतियों और बाधाओं की एक श्रृंखला बनाई, जिससे दरों और कीमतों को बढ़ाया, देरी और रहने के समय में वृद्धि हुई, और सेवा विश्वसनीयता को कम कर दिया। जैसा कि आईएचएस मार्किट सप्लायर्स (चित्रा 2क) वितरण समय सूचकांक द्वारा दिखाया गया है, यूएस और यूरोपियन यूनियन (ईयू) में वितरण समय ने 20102 के बाद से अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है।

चित्र 2क: वितरण समय सूचकांक के लिए क्रय प्रबंधक का उप-सूचकांक



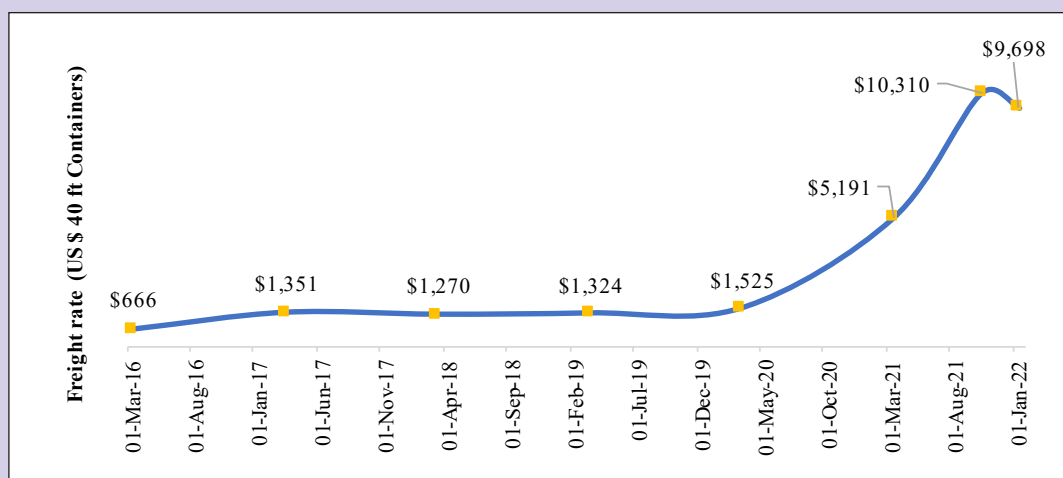
स्रोत: आईएचएस मार्केट।

नोट: पीएमआई = परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। 50 से ऊपर की रीडिंग तेजी से वितरण समय का संकेत देती है, 50 सिग्नल पर कोई बदलाव नहीं, और 50 से नीचे की रीडिंग धीमी गति का संकेत देती है।

शिपिंग कंटेनर (जल परिवहन पात्र) की कमी और बढ़ती व्यापार लागत

कंटेनर की कमी के तनाव को ड्रयूरी³ के समग्र विश्व कंटेनर सूचकांक⁴ में रखा जा सकता है। सूचकांक 20 जनवरी, 2022 तक प्रति 40 फिट कंटेनर के लिए यूएस डॉलर 9,698.33 है। यह पांच साल के औसत से 6,656 अमेरिकी डॉलर अधिक है और एक साल पहले की तुलना में 82 प्रतिशत अधिक है। लंबी अवधि के लिए कीमतों में इतनी महत्वपूर्ण वृद्धि यह दर्शाती है कि वैश्विक कंटेनर बाजार में व्यवधान अभी खत्म नहीं हुआ है जिससे वैश्विक समुद्री व्यापार का प्रभावित होना जारी रहेगा।

चित्र 2ख: विश्व कंटेनर सूचकांक (यूएस+ प्रति 40 फीट कंटेनर)



स्रोत: ड्रयूरी सप्लाय चैन एडवाइजर्स (2022)

³https://m.rbi.org.in/Scripts/BB_ViewBulletin.aspx?Id=20628

⁴समुद्री परिवहन पर स्वतंत्र थिंक टैंक

<https://www.drewry.co.uk/supply-chain-advisors/supply-chain-esxpertise/world-container-index-assessed-by-drewry>

⁴आठ प्रमुख पूर्व-पश्चिम ट्रेडों का भारत माल भाड़ा मूल्यांकन।

इसके अलावा, प्रमुख वैश्विक समुद्री मार्गों पर माल ढुलाई की कीमतों में इसी अवधि के दौरान ऊपर की ओर रुझान देखा गया है। नीचे दी गई तालिका 2क प्रमुख मार्गों के लिए पिछले वर्ष से कीमतों और प्रतिशत परिवर्तन (वर्ष-दर-वर्ष) को दर्शाती है।

तालिका 2क: प्रमुख मार्ग से स्पॉट फ्रेट दरें

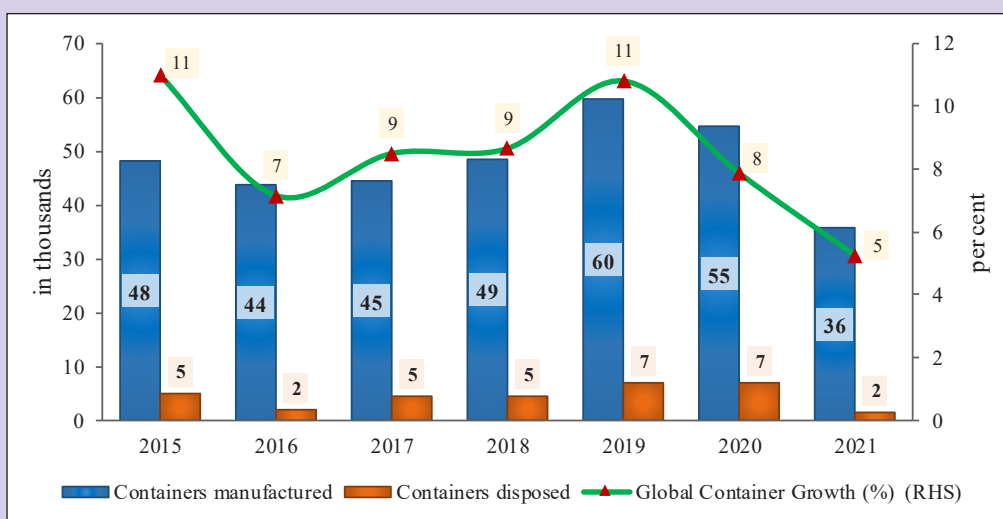
मार्ग	20-जनवरी-22 (अमरीकी डॉलर) की स्थिति के अनुसार	वर्ष-दर-वर्ष बदलाव (प्रतिशत)
संयुक्त सूचकांक	9,698	82
शंघाई - रॉटरडैम	14,053	55
रॉटरडैम - शंघाई	1,452	3
शंघाई - जेनोआ	12,794	46
शंघाई - लॉस एंजिलस	11,197	168
लॉस एंजिलस - शंघाई	1,262	138
शंघाई - न्यू यॉर्क	13,987	115
न्यूयॉर्क - रॉटरडैम	1,245	93
रॉटरडैम - न्यूयॉर्क	6,292	176

स्रोत: ड्यूरी, 2022

कंटेनरों की कमी ने भारतीय समुद्री व्यापार को भी प्रभावित किया है। वाणिज्य और व्यापार मंत्रालय के तहत स्थापित फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन के अनुसार, कंटेनरों की कमी के कारण समुद्री माल भाड़ा 300 प्रतिशत से 350 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

इसके अलावा, 2019 के बाद से नए कंटेनरों का उत्पादन धीमा हो गया है (चित्र 2ग)। साथ ही, इसी अवधि के दौरान कंटेनरों के निपटान में भी वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार, कंटेनरों में समग्र वृद्धि 2019 में 11 प्रतिशत से गिरकर 2021 में 5 प्रतिशत हो गई है। जब तक दुनिया भर में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, यह एक सतत समस्या बनी रहेगी।

चित्र 2ग: कंटेनरों का निर्माण और निपटान



स्रोत: 2021 वैश्विक टैंक कंटेनर बेड़े सर्वेक्षण, अंतर्राष्ट्रीय टैंक कंटेनर संगठन

मोटर उद्योग में सेमीकंडक्टर (अर्धचालक) उद्योग की आपूर्ति समस्याओं का असर

निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स 2021 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्धचालक उद्योग में आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान 169 से अधिक उद्योगों में फैल गया है। अर्धचालकों के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है और इसके पूरा होने की औसत अवधि 6-9 महीने होती है। इसके अलावा, इसका लगभग 18-20 सप्ताह का काफी लंबा उत्पादन चक्र है, इसलिए, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से बहाली धीमी और महंगी प्रक्रिया साबित होगी।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स का मोटर उद्योग द्वारा वर्धित मूल्य में लगभग 4.7 प्रतिशत हिस्सा है। पूर्ति में देरी के साथ, ऑटोमोबाइल उद्योग में 2021 के लिए औसत लीड समय का वैश्विक स्तर लगभग 14 सप्ताह हो गया है। भारत ने मोटर क्षेत्र में भी इसी तरह के रुझान का अनुभव किया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (एसआईएम) के आंकड़ों के अनुसार, कार निर्माताओं ने दिसंबर 2021 में घरेलू बाजार में 219,421 यात्री वाहनों की बिक्री की, जो कि 13 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) कम है। यह मांग की समस्या नहीं है बल्कि आपूर्ति पक्ष की समस्या है। विभिन्न कार निर्माता की वेबसाइटों की जानकारी से पता चलता है कि कुल मिलाकर 7 लाख से अधिक ऑर्डर, दिसंबर 2021 तक लम्बित है।

आपूर्ति पक्ष में सुधार

1.39 भारत की आर्थिक प्रतिक्रिया की एक और विशिष्ट विशेषता मांग प्रबंधन पर पूर्ण निर्भरता के बजाय आपूर्ति पक्ष सुधारों पर जोर देना है। इन आपूर्ति-पक्ष सुधारों में कई क्षेत्रों का विनियमन, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, श्रृंखला परीक्षण जैसे पुराने मुद्दों को हटाना, निजीकरण, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन आदि शामिल हैं। इनमें से कुछ को तालिका 7 में सूचीबद्ध किया गया है और संबंधित अध्यायों में विस्तार से चर्चा की गई है। यहां तक कि सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि को मांग और आपूर्ति प्रतिक्रिया दोनों के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि यह भविष्य के विकास के लिए बुनियादी ढांचे की क्षमता बनाता है।

1.40 एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान चर्चा की गई है, वह है 'प्रक्रिया सुधार'। विनियमन और प्रक्रिया सुधारों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। पूर्व किसी विशेष गतिविधि से सरकार की भूमिका को कम करने या हटाने से संबंधित है। इसके विपरीत, उत्तरार्द्ध मोटे तौर पर उन गतिविधियों के लिए प्रक्रिया के सरलीकरण और सुगमता से संबंधित है जहां एक सुविधाकर्ता या नियामक के रूप में सरकार की उपस्थिति आवश्यक है। अध्याय 2 सार्वजनिक खरीद नीति में किए गए सुधारों पर चर्चा करता है- मानक नियमित उपयोग की वस्तुओं के लिए 2016 में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) का शुभारंभ और गैर-मानक वस्तुओं और परियोजनाओं के लिए अक्टूबर 2021 में जारी किए गए नए खरीद दिशानिर्देश। अध्याय 4 कॉरपोरेट्स के लिए स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया के सरलीकरण और सीमा पार दिवाला प्रक्रिया के लिए एक मानक प्रक्रिया को संस्थागत बनाने की आवश्यकता पर चर्चा करता है। इसी तरह, अध्याय 9 में दूरसंचार क्षेत्र में ड्रोन नियमों और सुधारों के सरलीकरण और पेटेंट आवेदन व्यवस्था में सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा की गई है।

1.41 भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया में आपूर्ति-पक्ष पर दिया गया जोर दो महत्वपूर्ण विचारों से प्रेरित है। सबसे पहले, भारतीय नीति-निर्माताओं ने यात्रा-प्रतिबंधों, लॉकडाउन और आपूर्ति-श्रृंखला के टूटने के कारण होने वाले व्यवधानों को अर्थव्यवस्था के आपूर्ति-पक्ष में रुकावट के रूप में देखा। हालांकि इसने मांग को भी कम कर दिया, महामारी से संबंधित आर्थिक मंदी को केवल मांग की समस्या के रूप में देखना सही नहीं है जैसा कि अधिकांश आर्थिक चक्रों के साथ होता है। दूसरा, कोविड के बाद की दुनिया कई तरह के कारकों - प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, उपभोक्ता व्यवहार, भू-राजनीति, आपूर्ति-श्रृंखला, जलवायु परिवर्तन आदि से प्रभावित होगी। ये सभी कारक एक दूसरे के साथ अप्रत्याशित तरीके भी जुड़े होंगे। इसलिए, कोविड के बाद की अर्थव्यवस्था केवल पूर्व-कोविड अर्थव्यवस्था की फिर से मुद्रास्फीति नहीं होगी। केवल मांग के उपायों के साथ इसे वापस बनाना कोई समाधान नहीं है।

1.42 भारत की आपूर्ति-पक्ष रणनीति में दो सामान्य विषय हैं: (i) सुधार जो कोविड के बाद की दुनिया की दीर्घकालिक अप्रत्याशितता से निपटने के लिए लचीलेपन और नवाचार में सुधार करते हैं। इसमें कारक बाजार सुधार शामिल हैं; अंतरिक्ष, ड्रोन, भू-स्थानिक मानचित्रण, व्यापार वित्त फैक्ट्रिंग जैसे क्षेत्रों का विनियमन; प्रक्रिया सुधार जैसे सरकारी खरीद और दूरसंचार क्षेत्र में; पूर्वव्यापी कर जैसे पुराने मुद्दों को हटाना; निजीकरण और मुद्रीकरण, भौतिक बुनियादी ढांचे का निर्माण, और इसी तरह कारक बाजार शामिल है। (ii) भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन में सुधार लाने के उद्देश्य से सुधार है। ये जलवायु/पर्यावरण संबंधी नीतियों से लेकर; सामाजिक आधारभूत संरचना जैसे नल के पानी, शौचालय, बुनियादी आवास, गरीबों के लिए बीमा, आदि का सार्वजनिक प्रावधान; आत्मानिर्भर भारत के तहत प्रमुख उद्योगों के लिए समर्थन; विदेशी व्यापार समझौतों, और इसी तरह पारस्परिकता पर एक मजबूत जोर है। कुछ टिप्पणीकारों ने पुराने स्कूल संरक्षणवाद की वापसी के लिए आत्मानिर्भर भारत दृष्टिकोण की तुलना की है। इससे दूर, आर्थिक लचीलेपन पर ध्यान देना अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति-श्रृंखला की अनियमितताओं की व्यावहारिक मान्यता है (बॉक्स 2 में चर्चा देखें)।

1.43 जैसा कि पाठक ने अनुमान लगाया होगा, प्लचीलापन और प्सहज दो आयामी दृष्टिकोण महामारी की अल्पकालिक प्रतिक्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली बारबेल रणनीति के अनुरूप हैं। यह आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों - घटनाओं के भविष्य के प्रवाह के बारे में अनिश्चितता जैसे एक ही मुद्दे से निपटने का प्रयास कर रहे हैं।

तालिका 7: प्रमुख आपूर्ति पक्ष उपाय/सुधार

क्षेत्र	उपाय/सुधार
उद्योग	<ul style="list-style-type: none"> 13 क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है जिसमें (i) ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, (ii) फार्मास्युटिकल ड्रग्स, (iii) स्पेशलिटी स्टील, (iv) टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, (v) इलेक्ट्रॉनिक / टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, (vi) श्वेत सामान (एसी और एलईडी), (vii) खाद्य उत्पाद, (viii) कपड़ा उत्पाद: एमएमएफ खंड और तकनीकी वस्त्र, (xi) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, (x) उन्नत रसायन सेल बैटरी, (xi) चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन, (xii) मोबाइल निर्माण और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक और (xiii) महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री / दवा मध्यस्थ और सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री शामिल है। कर निश्चितता और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए पूर्वव्यापी कर को निरस्त कर दिया गया था।
बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) क्षेत्र	<p>अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के लिए उदारीकृत दिशानिर्देश</p> <ul style="list-style-type: none"> ओएसपी की स्पष्ट परिभाषा: नए दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता उन संस्थाओं तक सीमित है जो अपने ग्राहकों को 'आवाज पर आधारित बीपीओ सेवाएं' प्रदान करती हैं। आवाज पर आधारित बीपीओ सेवाओं को कॉल सेंटर सेवाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत में ओएसपी केंद्रों के लिए पंजीकरण की आवश्यकता को हटाना। इन दिशा-निर्देशों के तहत किसी भी सुविधा या व्यवस्था के लिए किसी बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी के बीच का अंतर हटा दिया गया। घर और दूरस्थ स्थानों से काम करने की अनुमति: घर/कहीं भी एजेंटों को ओएसपी केंद्र के दूरस्थ एजेंट के रूप में माना जाएगा। वायरलाइन/वायरलेस पर ब्रॉडबैंड सहित किसी भी तकनीक का उपयोग करके रिमोट एजेंटों के बीच इंटरकनेक्शन की अनुमति है। रिमोट एजेंट अब ओएसपी केंद्र से जुड़ने की आवश्यकता के बिना ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज (ईपीएबीएक्स) / केंद्रीकृत ईपीएबीएक्स से सीधे जुड़ सकता है।

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ एक ही या असंबंधित कंपनी के दो या दो से अधिक ओएसपी केंद्रों के बीच इंटरकनेक्शन की अब अनुमति है। ➤ ओएसपी के बीच अवसंरचना साझा करने की अब अनुमति है। दिशानिर्देश विदेशी स्थानों पर ईपीएबीएक्स के उपयोग की अनुमति देते हैं।
<p>दूरसंचार</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● संरचनात्मक सुधार <ul style="list-style-type: none"> ➤ समायोजित सकल राजस्व का युक्तिकरण: गैर-दूरसंचार राजस्व को समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा से बाहर रखा जाएगा। ➤ बैंक गारंटी को युक्तिसंगत बनाना: लाइसेंस शुल्क और अन्य समान शुल्कों के लिए बैंक गारंटी आवश्यकताओं में भारी कमी। अब से आयोजित नीलामियों के लिए, किशत भुगतान सुरक्षित करने के लिए किसी बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। ➤ ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है और लाइसेंस शुल्क या स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) के विलंबित भुगतान से दंड को हटा दिया गया है। ➤ दूरसंचार क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। ➤ भविष्य की स्पेक्ट्रम नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) नहीं। ➤ स्पेक्ट्रम शेयरिंग को बढ़ावा: स्पेक्ट्रम शेयरिंग के लिए 0.5 फीसदी का अतिरिक्त एसयूसी हटा दिया गया। ● प्रक्रिया सुधार <ul style="list-style-type: none"> ➤ व्यापार करने में सुगमता को बेहतर बनाने के लिए वायरलेस उपकरणों के आयात के लिए सीमा शुल्क निकासी की आवश्यकता को हटा दिया गया और स्व-घोषणा के साथ बदल दिया गया। ➤ टावरों को स्थापित करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन मंजूरी प्रक्रिया पर स्थायी सलाहकार समिति दूरसंचार विभाग के सरल संचार पोर्टल पर स्व-घोषणा/स्वचालित समयबद्ध अनुमोदन के माध्यम से होगी। ➤ ऐप/वेब-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से अब स्व-केवाईसी की अनुमति है। ➤ पेपर कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म को डेटा के डिजिटल स्टोरेज से बदल दिया जाएगा। ➤ नीलामी कलैण्डर नियत: स्पेक्ट्रम नीलामी सामान्यतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में आयोजित की जाती है। ● इसके साथ ही, समायोजित सकल राजस्व निर्णय या पिछली नीलामी (2021 की नीलामी को छोड़कर) में खरीदे गए स्पेक्ट्रम के देय भुगतान से उत्पन्न होने वाली बकाया राशि के भुगतान पर अधिस्थगन/आस्थगन सहित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की तरलता आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए थे।
<p>सार्वजनिक खरीद नीति</p>	<p>अक्टूबर 2021 में खरीद और परियोजना प्रबंधन के लिए नए दिशानिर्देशों की घोषणा की गई थी</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ कार्यों और गैर-परामर्श सेवाओं के लिए बोलीदाताओं के चयन के लिए गुणवत्ता-सह-लागत आधारित चयन की भी अनुमति है।

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भुगतान करने के लिए सख्त समय सीमा: नए दिशानिर्देश बिल जमा करने के 10 कार्य दिवसों के भीतर उठाए गए बिलों के 75 प्रतिशत या उससे अधिक के भुगतान को समय पर जारी करने का प्रावधान करते हैं। शेष बिल भुगतान 28 कार्य दिवसों के भीतर अंतिम जाँच के बाद किया जाना है। ➤ मध्यस्थता और विवाद समाधान: खरीद अधिकारी किसी भी आदेश के खिलाफ अपील दायर करने से पहले मामले की समीक्षा करने के लिए एक विशेष बोर्ड/समिति का गठन करते हैं। सरकार ने उन मामलों में जहां एक खरीद एजेंसी ने एक मध्यस्थ पंचाट को चुनौती दी है, बैंक गारंटी के खिलाफ ठेकेदारों को 75 प्रतिशत राशि जारी करने की अनुमति दी है।
<p>विमानन</p>	<p>ड्रोन नियम (अगस्त 2021 में घोषित)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ नियमों की विस्तारित प्रयोज्यता: 500 किलोग्राम तक के ड्रोन अब नियमों के अधीन हैं, जबकि पहले की सीमा 300 किलोग्राम थी। ➤ भरे जाने वाले कुल फॉर्मों के साथ कई स्वीकृतियां 25 से घटाकर 5 कर दी गईं। ➤ फीस के प्रकार को 72 से घटाकर 4 किया गया। ➤ भुगतान की जाने वाली फीस की मात्रा को काफी कम कर दिया गया है और ड्रोन के आकार से अलग कर दिया गया है। ➤ पूर्व सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता को हटाना। ➤ भारत में ड्रोन के स्वामित्व, निर्माण या उससे निपटने वाली सभी विदेशी संस्थाओं पर पहले के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। ➤ माइक्रो ड्रोन (गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए) और नैनो ड्रोन के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ➤ ड्रोन संचालन का विस्तारित क्षेत्र: डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर एक इंटरैक्टिव मानचित्र मानचित्र पर रंग-कोडित क्षेत्रों को निर्दिष्ट करता है अर्थात् हरा, पीला और लाल, जो क्रमशः मुक्त क्षेत्रों को, पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, और नो-फ्लाई जोन को दर्शाता है। हरित श्रेणी के तहत मुक्त रूप से सुलभ हवाई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों की परिधि को भी उदार बनाया गया है।
<p>वित्तीय क्षेत्र</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● बैंकिंग: जमा बीमा में सुधार <ul style="list-style-type: none"> ➤ जमा बीमा प्रपत्र में ₹ 1 लाख बढ़ाकर ₹ 5 लाख प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक की वृद्धि। इससे मार्च 2021 के अंत में कुल खातों की संख्या का 98.1 प्रतिशत पूरी तरह से सुरक्षित हो गया और कुल जमा राशि का 50.9 प्रतिशत बीमा किया गया। ➤ अंतरिम भुगतान की शुरुआत: जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा उन बैंकों के जमाकर्ताओं को अंतरिम भुगतान किया जाएगा जिनके लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत आरबीआई द्वारा कोई प्रतिबंध / स्थगन लगाया गया है जिसके परिणामस्वरूप जमाकर्ताओं को अपनी बचत तक पहुंचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ➤ जमाकर्ताओं को अंतरिम भुगतान प्रदान करने के लिए अधिकतम 90 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है। ● फैक्टरिंग इकोसिस्टम में विस्तार: एनबीएफसी की पहले की स्थिति जिसका मुख्य व्यवसाय फैक्टरिंग था, को हटा दिया गया है और अब सभी एनबीएफसी को फैक्टरिंग व्यवसाय करने की अनुमति है।

<p>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● एमएसएमई की संशोधित परिभाषा: <ul style="list-style-type: none"> ➤ विनिर्माण और सेवा एमएसएमई के बीच अंतर को हटाना। ➤ उद्योग और सेवा क्षेत्र में एमएसएमई की ऊपर की ओर संशोधित परिभाषा। नई परिभाषा के अनुसार ऊपरी सीमा इस प्रकार है: <table border="1" data-bbox="554 373 1358 609"> <thead> <tr> <th></th> <th>संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश</th> <th>वार्षिक कारोबार</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सूक्ष्म</td> <td>< ₹1 करोड़</td> <td>< ₹ 5 करोड़</td> </tr> <tr> <td>लघु</td> <td>< ₹10 करोड़</td> <td>< ₹ 50 करोड़</td> </tr> <tr> <td>मध्यम</td> <td>< ₹ 50 करोड़</td> <td>< ₹ 250 करोड़</td> </tr> </tbody> </table> ● एमएसएमई के लिए सरलीकृत पंजीकरण प्रक्रिया। ● सार्वजनिक खरीद नीति के तहत सूक्ष्म और लघु उद्योगों (एमएसई) के लिए बाजार पहुंच बढ़ाना: सभी केंद्रीय मंत्रालयों, सरकारी विभागों और सीपीएसई को एमएसई से माल और सेवाओं की अपनी वार्षिक आवश्यकताओं का 25 प्रतिशत खरीदना आवश्यक है। इसके अलावा, ब 200 करोड़ तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं। 		संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश	वार्षिक कारोबार	सूक्ष्म	< ₹1 करोड़	< ₹ 5 करोड़	लघु	< ₹10 करोड़	< ₹ 50 करोड़	मध्यम	< ₹ 50 करोड़	< ₹ 250 करोड़
	संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश	वार्षिक कारोबार											
सूक्ष्म	< ₹1 करोड़	< ₹ 5 करोड़											
लघु	< ₹10 करोड़	< ₹ 50 करोड़											
मध्यम	< ₹ 50 करोड़	< ₹ 250 करोड़											
<p>अंतरिक्ष और भू-स्थानिक क्षेत्र</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● निजी क्षेत्र की बढ़ी हुई भागीदारी के लिए पारंपरिक उपग्रह संचार और सुदूर संवेदन क्षेत्रों को उदार बनाना। ● मानचित्रों सहित भू-स्थानिक डेटा के निर्माण, अधिग्रहण और उपयोग के लिए दिशानिर्देश: भू-स्थानिक डेटा को पहले कड़ाई से विनियमित किया गया था और ऐसे डेटा के उपयोग के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक था। अब दिशानिर्देशों को उदार बनाया गया है: <ul style="list-style-type: none"> ➤ स्व-प्रमाणन व्यवस्था की शुरुआत: भू-स्थानिक डेटा और मानचित्रों के उपयोग के लिए पूर्व अनुमोदन या लाइसेंस प्राप्त करने के विपरीत, सभी संस्थाओं को अब दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए एक स्व-प्रमाणन प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है। ➤ प्रतिबंधित क्षेत्रों में छूट: पिछली शासन व्यवस्था के तहत प्रतिबंधित क्षेत्रों के विपरीत, अत्यधिक संवेदनशील स्थानों की विशिष्ट विशेषताओं के लिए मानचित्रण गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं। ➤ निर्यात प्रतिबंधों पर छूट: दिशानिर्देश 1:100 रिजॉल्यूशन तक के रिजॉल्यूशन वाले मानचित्रों के निर्यात की अनुमति देते हैं, जिससे 1:250000 की पिछली सीमा में ढील दी जाती है। ➤ सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित डेटा तक सीधी पहुंच: दिशानिर्देशों के लिए सभी भारतीय संस्थाओं के लिए स्वतंत्र रूप से सुलभ होने के लिए, भारतीय सर्वेक्षण द्वारा उत्पादित डेटा सहित सार्वजनिक धन का उपयोग करके उत्पादित सभी भू-स्थानिक डेटा की आवश्यकता होती है। 												
<p>विनिवेश</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● नई सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति और संपत्ति मुद्राकरण रणनीति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रणनीतिक विनिवेश के लिए नई नीति है सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक उद्यमों को रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में निजीकरण की नीति और रणनीतिक क्षेत्रों में भी न्यूनतम उपस्थिति के साथ किया गया है। 												

	<p>चिन्हित रणनीतिक क्षेत्र: (i) परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा; (ii) परिवहन और दूरसंचार; (iii) बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज; और (iv) बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं हैं।</p> <p>एयर इंडिया का निजीकरण।</p> <ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन <p>चार साल (2021-22 से 2024-25) की अवधि में ₹ 6 लाख करोड़ का बुनियादी ढांचा निवेश</p> <p>सड़क, रेलवे, बिजली, तेल और गैस पाइपलाइन और दूरसंचार सहित शीर्ष 5 क्षेत्रों में कुल मूल्य का लगभग 83 प्रतिशत हिस्सा है।</p> <p>अब तक, सीपीएसई ने मुद्राकरण के लिए 3400 एकड़ भूमि और अन्य गैर-प्रमुख संपत्तियों को संदर्भित किया है।</p>
श्रम सुधार	<ul style="list-style-type: none"> केंद्र सरकार ने चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया।
रक्षा	<ul style="list-style-type: none"> आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के निगमीकरण को मंजूरी दी गई और 7 नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बनाए गए। रक्षा क्षेत्र में स्वतः अनुमोदित मार्ग से 74 प्रतिशत तक और सरकारी मार्ग से 100 प्रतिशत तक एफडीआई बढ़ाया गया

विकास दृष्टिकोण

1.44 2020-21 में 7.3 प्रतिशत के संकुचन के बाद, भारतीय अर्थव्यवस्था के 2021-22 में वास्तविक रूप से 9.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है (पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार)। व्यापक वैक्सीन कवरेज, आपूर्ति-पक्ष सुधारों से लाभ और नियमों में ढील, मजबूत निर्यात वृद्धि, और पूंजीगत खर्च को बढ़ाने के लिए राजकोषीय उपलब्धता द्वारा 2022-23 में विकास को समर्थित किया जाएगा। आने वाला वर्ष भी निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि के लिए अच्छी तरह से तैयार है, जिसमें वित्तीय प्रणाली अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए सहायता प्रदान करने के लिए अच्छी स्थिति में है। इस प्रकार, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 2022-23 में वास्तविक रूप से 8.0-8.5 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। यह अनुमान इस धारणा पर आधारित है कि आगे कोई दुर्बल करने वाली महामारी संबंधी आर्थिक व्यवधान नहीं होगा, मानसून सामान्य रहेगा, प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा वैश्विक तरलता की निकासी मोटे तौर पर व्यवस्थित होगी, तेल की कीमतें यूएस + 70- + 75 / की सीमा में होंगी। इस, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान वर्ष के दौरान लगातार कम होंगे।

1.45 उपरोक्त परिवर्तन विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के 2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी विकास दर क्रमशः 8.7 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत के नवीनतम पूर्वानुमानों के साथ तुलनीय है। 25 जनवरी, 2022 को जारी आईएमएफ के नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक विकास अनुमानों के अनुसार, भारत की वास्तविक जीडीपी 2021-22 और 2022-23 दोनों में 9 प्रतिशत और 2023-24 में 7.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। यह भारत को इन सभी तीन वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में पेश करता है (तालिका 8)।

तालिका 8: विश्व आर्थिक आउटलुक अनुमानों का अवलोकन

देश/देश समूह	वर्ष दर वर्ष (प्रतिशत परिवर्तन, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)			
	आकलन		अनुमान	
	2020	2021	2022	2023
विश्व उत्पादन	-3.1	5.9	4.4	3.8
विकसित अर्थव्यवस्थाएँ	-4.5	5.0	3.9	2.6
संयुक्त राज्य अमेरिका	-3.4	5.6	4.0	2.6
यूरो क्षेत्र	-6.4	5.2	3.9	2.5
जर्मनी	-4.6	2.7	3.8	2.5
फ्रांस	-8.0	6.7	3.5	1.8
इटली	-8.9	6.2	3.8	2.2
स्पेन	-10.8	4.9	5.8	3.8
जापान	-4.5	1.6	3.3	1.8
यूनाइटेड किंगडम	-9.4	7.2	4.7	2.3
कनाडा	-5.2	4.7	4.1	2.8
अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाएं*	-1.9	4.7	3.6	2.9
उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	-2.0	6.5	4.8	4.7
उभरते और विकासशील एशिया	-0.9	7.2	5.9	5.8
चीन	2.3	8.1	4.8	5.2
भारत**	-7.3	9.0	9.0	7.1
आसियान***	-3.4	3.1	5.6	6.0
उभरते और विकासशील यूरोप	-1.8	6.5	3.5	2.9
रूस	-2.7	4.5	2.8	2.1
लैटिन अमेरिका और कैरेबियन	-6.9	6.8	2.4	2.6
ब्राजिल	-3.9	4.7	0.3	1.6
मेक्सिको	-8.2	5.3	2.8	2.7
मध्य पूर्व और मध्य एशिया	-2.8	4.2	4.3	3.6
सऊदी अरब	-4.1	2.9	4.8	2.8
उप सहारा अफ्रीकी	-1.7	4.0	3.7	4.0
नाइजीरिया	-1.8	3.0	2.7	2.7
दक्षिण अफ्रीका	-6.4	4.6	1.9	1.4

स्रोत: आईएमएफ डब्ल्यूईओ (WEO), जनवरी 2022 अद्यतन स्थिति

*सात के समूह (कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका) और यूरो क्षेत्र के देशों को छोड़कर।

**भारत के लिए, डेटा और पूर्वानुमान वित्तीय वर्ष के आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं, वित्त वर्ष 2021/2022 अप्रैल 2021 से शुरू होता है। जनवरी 2022 डब्ल्यूईओ (WEO) की अद्यतन स्थिति के लिए, भारत के विकास अनुमान 2022 में 8.7 प्रतिशत और कैलेंडर वर्ष के आधार पर 2023 में 6.6 प्रतिशत हैं। ओमिक्रोन (Omicron) प्रकार के प्रभाव को तालिका में 2021 के कॉलम में कैप्चर किया गया है।

***इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम।

अनुबंध

80 उच्च आवृत्ति संकेतकों (एचएफआई) की सूची

- 1 10 साल का एएए निगमित बंधपत्र आय
- 2 10 साल की जी-सेक आय
- 3 8-कोर उद्योग सूचकांक
- 4 आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (अग्रिम अ.पीएस) लेनदेन
- 5 एटीएम निकासी
- 6 औसत दैनिक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी)
- 7 औसत खुदरा मूल्य (गेहूं, चावल, अरहर, चीनी, आलू, प्याज, टमाटर, मूंगफली, ताड़ का तेल, अंडे, दूध)
- 8 बाल्टिक शुष्क सूचकांक
- 9 बैंक जमा
- 10 क्षमता उपयोग
- 11 पूंजीगत व्यय
- 12 सीमेंट उत्पादन
- 13 वाणिज्यिक पत्र (सीपी)
- 14 कॉर्पोरेट क्षेत्र मुनाफा
- 15 सीपीआई
- 16 सीपीआई कोर
- 17 सीपीआई भोजन
- 18 कच्चा तेल भारतीय बॉस्केट
- 19 क्रूडप्राइस ब्रेंट, दुबई, डब्ल्यूटीआई
- 20 प्रचलन में मुद्रा
- 21 डीमैट खाते
- 22 घरेलू ऑटो बिक्री
- 23 घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री
- 24 घरेलू ट्रैक्टर की बिक्री
- 25 घरेलू हवाई यात्री यातायात
- 26 ईपीएफओ- नेट सब्सक्राइबर बकाया

27	ई-वे बिल जनरेट किया गया
28	विनिमय दर
29	बाहरी वाणिज्यिक उधार
30	उर्वरकों की बिक्री
31	विदेशी मुद्रा भंडार
32	ईंधन की खपत
33	सरकारी बाजार उधार
34	वैश्विक पीएमआई समग्र
35	सकल एफडीआई
36	सकल कर राजस्व (केंद्र सरकार)
37	जीएसटी संग्रह
38	आवास प्रबंध की शुरूआत
39	आवास बिक्री
40	आईआईपी सामान्य सूचकांक, उपभोक्ता के लिए टिकाउ वस्तुएं, उपभोक्ता गैर-टिकाउ वस्तुएं
41	वस्तु निर्यात/आयात
42	मनरेगा का काम सृजित
43	मनरेगा के काम की मांग
44	पैसे की आपूर्ति
45	प्राकृतिक गैस उत्पादन
46	शुद्ध एफडीआई
47	शुद्ध एफपीआई
48	शुद्ध तरलता अंतःक्षेपण
49	अमेरिकी डॉलर की शुद्ध खरीद (+)/बिक्री (-)
50	निफ्टी/सेंसेक्स
51	सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर)
52	गैर-खाद्य ऋण
53	गैर तेल निर्यात
54	गैर तेल गैर सोने का आयात
55	दूरसंचार ग्राहकों की संख्या

56	पीएमआई विनिर्माण
57	पीएमआई सेवाएं
58	पोर्टकार्गो यातायात
59	बिजली की खपत
60	प्राथमिक निर्गम
61	कॉरपोरेट बांडों का निजी नियोजन
62	रेल माल यातायात
63	रेल यात्रियों की कमाई
64	आरबीआई: वर्तमान स्थिति सूचकांक
65	आरबीआई: फ्यूचर एक्सपेक्शन इंडेक्स
66	वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (सं.अ.ईआर)
67	रियल एस्टेट मूल्य सूचकांक-आरबीआई
68	कुल खुदरा वित्तीय लेनदेन (एनपीसीआई)
69	दोपहिया/तिपहिया वाहनों की बिक्री
70	क्षेत्र-वार निफ्टी सूचकांक: खपत, एफएमसीजी, अवसंरचना, रियल एस्टेट, धातु
71	क्षेत्रीय बैंक साख
72	स्टील की खपत
73	इस्पात उत्पादन
74	कुल मंडी आगमन (गेहूं, चावल, अरहर, चीनी, आलू, प्याज, टमाटर, मूंगफली, ताड़ का तेल)
75	यूपीआई लेनदेन
76	यूएस-डॉव जोन्स
77	वाहन पंजीकरण
78	नवीन बैंक उधार पर भारित औसत ब्याज दर
79	डब्ल्यूपीआई
80	विभिन्न परिपक्वताओं में प्रसारित आय